घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 277- शुक्रवार 07- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

राज्यसभा में खड़गे और रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक...बोलने के अधिकार को लेकर बढ़ा विवाद

नई दिल्ली,06 अगस्त 2026। संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई। खड़गे ने कहा- क्या अब मुझे किरेन रिजिजू से सीखना पड़ेगा। वे चेयरमैन के चेंबर में जाकर बोलते हैं कि रोज मैं ही यहां आकर बोलता हूं। अगर मैं नियम नहीं पढ़ूंगा तो क्या उनकी दी हुई चीजें पढ़ूं? खड़गे ने कहा- क्या बोलना है,कब बोलना है और कैसे बोलना है, यह तय करना मेरा अधिकार है। सत्ता पक्ष हमारे सांसदों का अपमान कर रहा है। मैं सिर्फ अमित शाह के संसद में आकर जवाब देने की मांग कर रहा हूं। इस सदन में जेटली जी ने खुद कहा था कि रुकावट लोकतंत्र का हिस्सा है। इस पर रिजिजू ने कहा...कांग्रेस अध्यक्ष विपक्ष के नए सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। एक ही मुद्दे पर बार-बार बोलकर समय बर्बाद कर रहे हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस के नए सांसद है। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं सदन में उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं। लेकिन दिक्कत यह है खेड़ा को अब तक वेलकम स्पीच देने तक का मौका नहीं मिला। भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही रोकने का आरोप लगाया।

राम मंदिर चढ़ावा,छात्रों पर कार्रवाई को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन

संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता तथा छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुई कठोर पुलिस कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। नवीन संसद एवं संविधान सदन के बीच विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग की।सांसदों ने गांधी प्रतिमा के निकट एकत्र होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित बर्बरता तथा राम मंदिर चढ़ावा मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। प्रदर्शनकारी सांसदों ने एक बड़ा पोस्टर हाथ में लिया हुआ था, जिस पर लिखा था, 'अमित शाह जवाब दो।' प्रदर्शन में कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद समेत कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसद शामिल थे। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ कठोरता से बल प्रयोग किया गया और सरकार इस मामले में जवाब देने से बच रही है।

सवालों पर चुप रहे रवि किशन साथ खड़े लोग बोले...मौन व्रत है...

संसद परिसर में मीडिया ने भाजपा सांसद रवि किशन से कई सवाल पूछे,लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह पूरे समय कैमरे के सामने चुपचाप खड़े रहे और मुस्कुराते रहे। इस दौरान उनके आसपास मौजूद कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा...बोल नहीं रहे हैं... मौन व्रत है। इससे पहले 4 अप्रैल को रवि किशन ने संसद परिसर में मीडिया के सवालों पर कहा था...आज हमारा मौन व्रत है। पंडित जी ने कहा है कि आज चुप रहिए। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वहीं 5 अप्रैल को वह फिर मीडिया के सामने आए, लेकिन इस बार मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। रवि किशन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अपने बयानों और डांस को लेकर चर्चा में हैं।

हंगामे के बीच लोकसभा से टैक्स बिल 2026 पास...

लोकसभा ने गुरुवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और अन्य विपक्षी दलों के सांसद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। लगातार शोर-शराबे के कारण सदन में सामान्य चर्चा नहीं हो सकी। इसी दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को सदन के समक्ष पेश किया और उसे पारित कराने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष के विरोध के बावजूद विधेयक बिना विस्तृत चर्चा के मंजूर कर लिया गया। सरकार के अनुसार इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना है। इसके साथ ही सरकार विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर निवेशकों का विश्वास बढ़ाना चाहती है। सरकार का मानना है कि स्पष्ट कर व्यवस्था और सरल प्रक्रियाओं से भारत में निवेश का माहौल बेहतर होगा तथा वैश्विक कंपनियां यहां उत्पादन गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अधिक उत्साहित होंगी। सदन में हंगामे के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई। इस दौरान जून 2026 में लागू अध्यादेश को अस्वीकार करने से संबंधित आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत

सांविधिक संकल्प को भी लोकसभा ने खारिज कर दिया। इसके अलावा विपक्षी सांसद के. राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा पेश किए गए संशोधन प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किए गए। अंत में सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। संशोधन विधेयक में भारत में कार्य करने वाले विदेशी फंड मैनेजरों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में विदेशी निवेश को भारत में प्रत्यक्ष कारोबार के रूप में नहीं माना जाएगा। सरकार ने उन विदेशी कंपनियों के लिए कर राहत की अवधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है, जो भारतीय फैक्ट्रियों को मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराती हैं तथा अनुबंध विनिर्माण के तहत उनके लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तैयार कराती हैं।

नीट-यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली,19 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली,06 अगस्त 2026। नीट-यूजी विवाद को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। परीक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में एक हलफनामा दाखिल किया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित हलफनामा अभी तक रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अदालत ने साफ किया कि हलफनामे में दर्ज कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे विचार और चर्चा की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पहले दाखिल किए गए हलफनामे का अध्ययन कर लें। अदालत ने कहा कि दस्तावेज में कई ऐसे तथ्य हैं, जिन पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने संकेत दिया कि परीक्षा प्रक्रिया और सुधारों से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इससे पहले 4 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर नीट परीक्षा व्यवस्था में किए गए सुधारों की जानकारी दी थी। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के संचालन में व्यापक बदलाव किए गए हैं, ताकि प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी कमियों को दूर किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि सरकार का उद्देश्य एक

ऐसी मजबूत और संस्थागत परीक्षा प्रणाली तैयार करना है, जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। सरकार के अनुसार,इन सुधारों का मकसद परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करना,संस्थागत अनुभव को बनाए रखना और प्रश्नपत्र लीक या अन्य अनियमितताओं की संभावनाओं को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को केंद्र सरकार से पूछा था कि भविष्य में नीट परीक्षा का आयोजन किस तरह किया जाएगा और परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे। अदालत के निर्देश के बाद शिक्षा मंत्रालय ने यह हलफनामा दाखिल किया। इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ी नई व्यवस्था और सुधारों की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के कामकाज की निगरानी करता है। वहीं नीट परीक्षा का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एनटीए के माध्यम से कराया जाता है।

जेन जी पर हमें भरोसा,वे स्मार्ट हैं....हमें उनकी बात समझनी चाहिए,उनसे बात नहीं हुई तभी तो आंदोलन हुआ : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत

नई दिल्ली,06 अगस्त 2026। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भगवत ने गुरुवार को युवा पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जेनरेशन जी और जेनरेशन अल्फा ईमानदार पीढियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीट परीक्षा के पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर पेलेट गन के इस्तेमाल के कारणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। जंतर-मंतर पर पेलेट गन के इस्तेमाल के बारे में बात करते हुए भगवत ने कहा, लाठी हमला क्यों हुआ? पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और हमें इसके पीछे का कारण जानना होगा।भगवत ने यह भी कहा कि जब उनकी पीढ़ी आज की पीढ़ी की उम्र की थी,तब लोग बड़ों की बात सीधे-सीधे सुन लेते थे। उन्होंने कहा...जब हम पीढ़ी की उम्र के थे,तब हम बड़ों की बात सुनते थे। हम कभी सवाल नहीं करते थे। अब पीढ़ी को तार्किक जवाब चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जेन जी और अल्फा ईमानदार पीढियां हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, नियम बनाना ठीक है,लेकिन वे तभी सफल होते हैं जब लोगों का नजरिया बदले। वरना, पहले से ही बहुत सारे कानून मौजूद हैं। कानून तभी असरदार होते हैं जब समाज उन्हें

अपनाए। सोशल मीडिया पर आप क्या हैं, इस बारे में सोचना जरूरी है क्योंकि लोग आपके काम को ही फॉलो करते हैं। इसलिए, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह देखें कि आपके फॉलोअर्स आपके काम (सोशल मीडिया पर) को फॉलो करके किसी गलत रास्ते पर न चले जाएं। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि नकली वीडियो बनाए जा सकते हैं और आपके या मेरे नाम से झूठे बयान फैलाए जा सकते हैं। इसलिए,सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय किसी भी कंटेंट पर तब तक भरोसा न करें जब तक कि उसे किसी भरोसेमंद स्रोत से वेरिफाई न कर लिया जाए। हमें सोशल मीडिया के मामले में खुद पर अनुशासन रखना होगा। वरना,अगर आप किसी चीज पर बैन लगाते हैं, तो वह धोखाधड़ी वाले बाजार में चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारतीय परंपरा में शास्त्रार्थ की समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें केवल वाद-विवाद नहीं, बल्कि पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष के माध्यम से किसी विषय के सभी पक्षों पर विचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब विभिन्न और परस्पर विरोधी मत भी सामने आते हैं,तभी किसी विषय की समग्र समझ विकसित होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में आंदोलन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहना उचित नहीं होगा कि लोगों को आंदोलन नहीं करना चाहिए,बल्कि आंदोलन संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉ। भीमराव आंबेडकर के विचारों में भी लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि यदि दिल्ली के लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं तो वे केवल विरोध करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे कोई न कोई वास्तविक चिंता या समस्या अवश्य होगी। उन्होंने कहा कि वे कोई अलग लोग नहीं हैं,बल्कि हमारे अपने और हमारी अगली पीढ़ी हैं। इसलिए उनके साथ अपनत्व, विश्वास और संवाद का संबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब संबंधों में विश्वास होता है, तभी सार्थक संवाद संभव होता है और दोनों पक्ष एक-दूसरे की बात को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं।

संघ प्रमुख ने कहा कि पीढ़ी ज़ेड के बारे में नकारात्मक धारणा बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनसे जब भी इस विषय पर प्रश्न पूछा गया,उन्होंने हमेशा यही कहा कि वर्तमान पीढ़ी की तुलना में नई पीढ़ी अधिक ईमानदार प्रतीत होती है।

पत्रकार तेजपाल को रेप केस में 10 साल की सजा

बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- 2 हफ्ते में सरेंडर करें 2013 में साथी पत्रकार ने आरोप लगाया था

पणजी,06 अगस्त 2026। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि वे 2 हफ्ते में सरेंडर करें। इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात

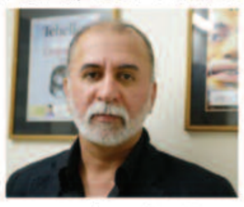

होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया। हाईकोर्ट के फैसले पर तेजपाल ने कहा...'हम फैसले से बहुत निराश हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ लोग तहलका और राजनीतिक बदले की भावना से 13 सालों से मेरे पीछे पड़े हैं। हमने 7.5 साल ट्रायल कोर्ट में केस लड़ा और बरी हुए थे।' हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की बजाय घटना के बाद पीड़ित महिला के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दिया। साथ ही, तेजपाल के माफी मांगने वाले ई-मेल जैसे अहम सबूतों को भी सही अहमियत नहीं दी। कोर्ट ने तेजपाल को आईपीएसी की धारा 376(2)(एफ), 376(2)(के), 354ए और 354बी के तहत दोषी माना है। ये धाराएं रेप, यौन उत्पीड़न और महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने से संबंधित हैं।

दुश्मन के एक साथ कई टारगेट तबाह करेगी अग्नि-4 मिसाइल,परीक्षण सफल...

उड़ान के दौरान अग्नि-4 ने अधिकतम सीमा तक लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया

नई दिल्ली,06 अगस्त 2026। भारत ने गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (एमआरबीएम) अग्नि-4 का सफल प्रक्षेपण करके एयरोस्पेस की दुनिया में धमाका कर दिया। ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से डीआरडीओ ने यह परीक्षण किया। मिसाइल ने अधिकतम सीमा तक जाकर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। अग्नि सीरीज की आधुनिक, घातक, सटीक और मीडियम रेंज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन के कई टारगेट एक साथ तबाह कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण (एनसीए) के सामरिक बल कमान के अधीन रात को किये गए प्रक्षेपण ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित किया। स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के तहत किए गए इस लॉन्च ने सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मापदंडों को

मान्य किया। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से दागी गई अग्नि-4 मिसाइल 1,000 किलोग्राम से लेकर 4,000 किलोमीटर तक पेलोड ले जा सकती है और इसे रोड-मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। 2012 में अग्नि-4 ने 20 मिनट में 3,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की थी। डीआरडीओ के मुताबिक अग्नि-4 मिसाइल को पहले अग्नि-2 प्राइम कहा जाता था। अग्नि मिसाइलों को डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया है। अग्नि-5 के साथ भारत की स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों ने एक लंबा सफर तय किया है। यह अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक, घातक, सटीक और मीडियम रेंज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की यह परमाणु मिसाइल एक साथ दुश्मन के कई टारगेट तबाह कर सकती है।

अग्नि-। सिंगल-स्टेज की मिसाइल है, जबकि 'अग्नि प्राइम' दो स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली मिसाइल है, जिसका तीसरा स्टेज मैन्यू रेबल रीएंट्री व्हीकल है। अग्नि परियोजना से जुड़े एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि इससे तीसरे स्टेज को दूर से नियंत्रित करके दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। डबल-स्टेज अग्नि प्राइम में एक कनस्तर संस्करण होगा, जिससे इसे सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से फायर किया जा सकता है।

2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर लगेगा चार्ज?

नई दिल्ली,06 अगस्त 2026। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संसद में 'भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2027' पेश किया है। इस बिल में मर्चेंट डिस्काउंट रेट को फिर से लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत 2000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर चार्ज लगाने की बात कही गई है। इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे और भ्रम फैलने लगे कि अब आम लोगों को यूपीआई से पेमेंट करने पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह 2000 रुपये की लिमिट क्या है और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा। सबसे पहले यह साफ कर लें कि इस नए प्रस्ताव का आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पडने वाला है।

अगर आप दूध, सब्जी, राशन, किराने का सामान खरीदते हैं या फिर ऑटो-टैक्सी का किराया चुकाते हैं, तो आपको पहले की तरह कोई चार्ज नहीं देना होगा। सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्ताव विशेष रूप से 2000 रुपये से अधिक के 'मर्चेंट ट्रांजेक्शन' (व्यापारिक लेन-देन) और बड़े कमर्शियल संस्थानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

अगर आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को 2000 रुपये या उससे ज्यादा की रकम भेजते हैं तो यह पूरी तरह से मुफ्त रहेगा।

अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत...झांसी जेल में बंद भाई अली से मिलने जा रहा था आबान

झांसी,06 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य व्यक्ति ने भी अपनी जान गंवाई, जबकि उनके तीन दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में आगे की सीट पर बैठे आबान अहमद एवं सोनू

खान के सिर में गंभीर चोट आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार सवार अहजम निवासी बादशाही मंडी (प्रयागराज), मोहम्मद जैद निवासी कोतवाली, उमर अहमद निवासी पूरा मुफ़्ती घायल हो गए। सभी प्रयागराज के रहने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा।

पीएम मोदी ने युवाओं से हैंडलूम-डे मनाने की अपील की

2 मिनट का वीडियो जारी किया,कहा...फ्रेंडशिप डे जैसा उत्साह दिखाइए...

नई दिल्ली,06 अगस्त 2026। पीएम मोदी ने गुरुवार रात इंस्टाग्राम पर रील शेयर की। उन्होंने कहा- साथियों, 7 अगस्त, 1905 हमें भूलना नहीं है। इस दिन देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन-जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सभी ने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से कपड़े बनाते हैं। और इसमें नई-नई वैरायटीज होती हैं। आप भी हैंडलूम की इस वैरायटी के साथ जीआरडब्ल्यूएम वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं।

हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इन छोटे-छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वंय हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें। उसका एक वीडियो बनाएं और देश-दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें। ताकि हमारे बुनकर परिवारों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे मनाएं। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यह पिछले 9 दिनों में पीएम मोदी का 5वां वीडियो है।

राम मंदिर चढ़ावा मामला : ट्रस्ट ने अब बहुमूल्य आभूषणों की कराई वीडियोग्राफी,वेबसाइट पर दिखाने की तैयारी

अयोध्या,06 अगस्त 2026। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ट्रस्ट अब भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या भ्रम से बचने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए बहुमूल्य आभूषणों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या शाखा के लॉकर में सुरक्षित रखे आभूषणों की विस्तृत वीडियोग्राफी कराई गई है। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद धनराशि

के साथ-साथ श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित बहुमूल्य आभूषणों के गायब होने की शिकायतें भी सामने आई थीं। हालांकि ट्रस्ट ने इन आरोपों को पहले ही निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। अब पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट ने सभी आभूषणों का वीडियो रिकॉर्ड तैयार कराया है। पिछले चार दिनों तक चली इस प्रक्रिया के दौरान ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन, हस्ताक्षरी जगदीश आफले, लेखाकार चंदन राय तथा भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय और क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सोने-चांदी के आभूषणों समेत अन्य बहुमूल्य उपहारों की अलग-अलग वीडियोग्राफी की गई। साथ ही अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन ने बैंक खातों की भी समीक्षा की।

संपादकीय

मौन शहर,मनमाने फैसले और आने वाली पीढ़ियों का सवाल

किसी भी शहर का भविष्य केवल इमारतों,सड़कों और सरकारी योजनाओं से तय नहीं होता। उसका भविष्य इस बात से तय होता है कि वहां लिए जाने वाले निर्णय कितने दूरदर्शी,पारदर्शी और जनहित पर आधारित हैं। दुर्भाग्य तब होता है,जब फैसले तो होते हैं,लेकिन जनता को उनकी जानकारी नहीं होती;योजनाएं बनती हैं,लेकिन स्थानीय लोगों से राय नहीं ली जाती; और विरोध की जगह समाज में एक खामोश स्वीकृति दिखाई देती है। बैकुंठपुर शहर को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठने लगे हैं। यदि शहर में विकास कार्य या प्रशासनिक निर्णय बिना पर्याप्त जनसंवाद,बिना विशेषज्ञों की राय और बिना स्थानीय आवश्यकताओं का समुचित आकलन किए जा रहे हैं,तो यह चिंता का विषय है। विकास का अर्थ केवल निर्माण कार्य नहीं होता,बल्कि ऐसा निर्णय लेना होता है जो वर्षों बाद भी शहर के हित में साबित हो।

इतिहास गवाह है कि कई शहरों ने जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की कीमत दशकों तक चुकाई है। कहीं जल निकासी की अनदेखी ने हर बरसात में बाढ़ की समस्या खड़ी कर दी,कहीं अतिक्रमण को नजरअंदाज करने से सड़कें सिकुड़ गई,तो कहीं बिना योजना के विकास ने शहर की पहचान ही बदल दी। उस समय भी बहुत लोग चुप थे,लेकिन बाद में वही चुप्पी सबसे बड़ी गलती मानी गई।

लोकतंत्र में मौन हमेशा सहमति का प्रतीक नहीं होता। कई बार लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। कई बार लोग टकराव से बचना चाहते हैं, और कई बार जानकारी के अभाव में भी चुप रहते हैं। लेकिन यदि हर निर्णय बिना सार्वजनिक चर्चा के स्वीकार कर लिया जाएगा, तो जवाबदेही का सवाल भी कमजोर पड़ जाएगा।

यह संपादकीय किसी एक निर्णय या किसी एक व्यक्ति की आलोचना नहीं है। यह उस सोच पर प्रश्न है जिसमें जनता की भागीदारी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। शहर किसी अधिकारी,जनप्रतिनिधि या विभाग का नहीं,बल्कि वहां रहने वाले प्रत्येक नागरिक का होता है। इसलिए शहर के भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों में नागरिकों की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। विरोध का अर्थ विकास रोकना नहीं होता। रचनात्मक सुझाव देना,कमियों की ओर ध्यान दिलाना और बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। यदि जनता हर निर्णय पर चुप रहे और बाद में केवल अफसोस करे, तो इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ता है।

आज बैकुंठपुर के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है–क्या शहर का विकास संवाद से होगा या केवल आदेशों से? क्या योजनाएं भविष्य को ध्यान में रखकर बनेंगी या केवल वर्तमान की जरूरतों तक सीमित रहेंगी?

आने वाली पीढ़ियां यह नहीं पूछेंगी कि उस समय कौन अधिकारी था या कौन जनप्रतिनिधि था। वे केवल इतना पूछेंगी–जब शहर का भविष्य तय हो रहा था,तब समाज चुप क्यों था?

पैसे पहुंचे...बेटियां नहीं...पिता की अंतिम विदाई ने रिश्तों पर उठाए सवाल

संजय सक्सेना
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

कुछ घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होतीं, बल्कि समाज के सामने एक आईना बनकर खड़ी हो जाती हैं। हरियाणा के सोनीपत से सामने आया 74 वर्षीय शिवचरण रामरतन गुप्ता का मामला भी ऐसी ही एक घटना है,जिसने परिवार, रिश्तों और बुजुर्गों की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी तीन बेटियों की परवरिश,पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए लगा दी,उसी पिता की आखिरी विदाई के समय बेटियां उनके पास नहीं पहुंच सकीं। अंतिम संस्कार वृद्धाश्रम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने किया,जबकि बेटियों ने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता की अंतिम यात्रा देखी। सोनीपत के वेस्ट राम नगर स्थित वृद्धाश्रम में रहने वाले शिवचरण गुप्ता कभी कपड़ा कारोबार से जुड़े सफल व्यापारी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया,परिवार को संभाला और अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाई। उनके लिए बेटियां कभी बेटे से कम नहीं रहीं। उन्होंने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया,उन्हें आगे बढ़ने के मौके दिए। उनकी दो बेटियां शिक्षिका बनीं और अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ीं। लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर जब शिवचरण गुप्ता को अपने परिवार और बेटियों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी,तब हालात बिल्कुल अलग नजर आए। बताया जाता है कि करीब 20 दिन पहले ही वृद्धाश्रम प्रबंधन ने उनकी तीनों बेटियों को पिता की बिगड़ती तबीयत की जानकारी दे दी थी। उन्हें बताया गया था कि शिवचरण गुप्ता बीमार हैं और उनकी हालत गंभीर है। वह अपनी बेटियों से मिलना चाहते थे, लेकिन कोई भी बेटी उनसे मिलने नहीं पहुंची। शिवचरण गुप्ता अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम में रहने आए थे। पत्नी के निधन के बाद वह पूरी तरह अकेले हो गए थे। उम्र,बीमारी और अकेलेपन के बीच उनका सबसे बड़ा सहारा उनकी बेटियों की आवाज थी। वृद्धाश्रम प्रबंधन के अनुसार, पहले वह फोन के जरिए बेटियों से बातचीत किया करते थे, लेकिन धीरे-धीरे बातचीत भी कम होती गई।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद शिवचरण गुप्ता ने अंतिम सांस ली। उनकी मौत की सूचना बेटियों को दी गई। वृद्धाश्रम की ओर से कहा गया कि अगर बेटियां आना चाहती हैं तो अंतिम संस्कार कुछ समय के लिए रोका जा सकता है,लेकिन बेटियों की ओर से आने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद वृद्धाश्रम प्रबंधन ने स्थानीय लोगों की मदद से अंतिम संस्कार कराने का फैसला किया जानकारी के मुताबिक, शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी अनिता नेपाल में रहती हैं और शिक्षिका हैं। दूसरी बेटी निशा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में

रहती हैं,जबकि तीसरी बेटी प्रिया मुंबई में रहती हैं। तीनों बेटियां अपने-अपने परिवारों में व्यस्त थीं। पिता की मौत के बाद भी वे सोनीपत नहीं पहुंचीं। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया देखी।अंतिम संस्कार के लिए बेटियों की ओर से 5100 रुपये भेजे गए और कहा गया कि पिता का अंतिम संस्कार विधि-विधान से किया जाए। बाद में अस्थियों को लेकर भी बेटियों ने आने में असमर्थता जताई और वृद्धाश्रम प्रबंधन से उन्हें गंगा में प्रवाहित करने का अनुरोध किया।यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। यह उस बदलते सामाजिक ढांचे की तस्वीर है, जहां रिश्तों की परिभाषा तेजी से बदल रही है। पहले संयुक्त परिवारों में बुजुर्ग घर के सबसे सम्मानित सदस्य हुआ करते थे। परिवार के छोटे-बड़े फैसलों में उनकी भूमिका होती थी। लेकिन बदलते समय में रोजगार,शहरों की दूरी और छोटी होती पारिवारिक संरचना ने बुजुर्गों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। भारत में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार,आने वाले वर्षों में देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। अनुमान है कि वर्ष 2036 तक भारत में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या करीब 23 करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी देश की लगभग हर सातवीं आबादी बुजुर्ग वर्ग में होगी। ऐसे में बुजुर्गों की देखभाल और उनका भावनात्मक सहारा समाज के सामने बड़ी चुनौती बनने वाला है।बुजुर्गों की समस्या सिर्फ पैसे या रहने की जगह की नहीं होती। सबसे बड़ी जरूरत होती है अपनापन,बातचीत और परिवार का साथ। कई बुजुर्गों के पास आर्थिक सुविधाएं होती हैं,लेकिन उनके पास अपना कहने वाला कोई नहीं होता। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें महंगे इलाज से ज्यादा अपनों का समय और प्यार चाहिए होता है।शिवचरण गुप्ता की कहानी में सबसे दर्दनाक पहलू यही है कि जिस पिता ने अपनी बेटियों के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि वह अपनी बेटियों को आखिरी बार देख सकें। लेकिन यह इच्छा अधूरी रह गई। हालांकि इस घटना का एक मानवीय पहलू भी सामने आया। जब परिवार के लोग दूर थे,तब वृद्धाश्रम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने इंसानियत का परिचय दिया। उन्होंने शिवचरण गुप्ता को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उन्होंने वह जिम्मेदारी निभाई जो अक्सर परिवार के लोग निभाते हैं। शिवचरण गुप्ता की आंखें भी दान की गईं। यानी उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आंखें किसी जरूरतमंद इंसान की जिंदगी में रोशनी ला सकती हैं। यह कदम बताता है कि एक इंसान का जीवन खत्म होने के बाद भी उसकी सोच और संवेदनाएं समाज के काम आ सकती हैं।सोनीपत की यह घटना आज के समाज से एक गंभीर सवाल पूछती है। क्या आधुनिक जिंदगी की भागदौड़ में रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं? क्या सफलता और व्यस्तता के बीच हम अपने बुजुर्गों को समय देना भूल रहे हैं? तकनीक ने हमें दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया है,लेकिन क्या वह उस भावनात्मक साथ की जगह ले सकती है जो किसी अपने की मौजूदगी से मिलता है?वीडियो कॉल पर किसी की अंतिम विदाई देखना आसान हो सकता है,लेकिन अंतिम समय में हाथ पकड़कर बैठना,आंखों के सामने विदा करना और अपनेपन का एहसास देना किसी भी तकनीक से संभव नहीं है। शिवचरण रामरतन गुप्ता की कहानी सिर्फ एक पिता की अधूरी इच्छा नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि रिश्तों को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं,बल्कि संवेदना की भी जरूरत होती है। जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते हुए अगर हम अपने बुजुर्गों का हाथ छोड़ देंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी यही सवाल हमारे सामने खड़ा कर सकती हैं।

क्या? समाज संवेदनहीनता की ओर बढ़ रहा हैं?

संजय एम.तराणेकर
इंदौर,मध्यप्रदेश

समाज की पहचान उसकी ऊँची इमारतों,चौड़ीसड़कों,बढ़ती अर्थव्यवस्था या आधुनिक तकनीक से नहीं होती। किसी भी सभ्यता का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि वह अपने बुजुर्गों, अपने माता-पिता और अपने रिश्तों के साथ कैसा व्यवहार करती है। जब कोई पिता, जिसने पूरी उम्र अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया,अपनी अंतिम यात्रा में अपनी ही संतान की प्रतीक्षा करता रह जाए,तब यह केवल एक परिवार का दुःख नहीं रहता;यह पूरे समाज की संवेदनहीनता का दस्तावेज़ बन जाता है।

हाल में सामने आई घटना,जिसमें एक वृद्ध पिता ने वृद्धाश्रम में अंतिम सांस ली और उनकी बेटियाँ अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हुई,बल्कि किसी ने पैसे भेजे और किसी ने वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार देखने की बात कही-यह समाचार पढ़कर मन अंदर तक विचलित हो जाता है। यह दृश्य केवल एक व्यक्ति की मृत्यु का नहीं,बल्कि रिश्तों की मरती हुई आत्मा का प्रतीक प्रतीत होता है।

हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हर सुविधा हमारी मुट्ठी में है। एक क्लिक पर पैसा भेजा जा सकता है,वीडियो कॉल की जा सकती है,दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ा जा सकता है। लेकिन विडंबना देखिए कि तकनीक ने दूरी तो घटा दी,पर दिलों के बीच की दूरियाँ बढ़ा दीं। आज बच्चों के पास माता-पिता के लिए महँगे उपहार हैं, लेकिन उनके साथ बैठने के लिए कुछ घंटे नहीं हैं। बैंक खाते भर गए हैं,लेकिन घरों के आँगन खाली हो गए हैं।

एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता? वह अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता है ताकि बच्चों के सपनों को पंख मिल सकें। वह अपनी भूख छिपाकर बच्चों का पेट भरता है। अपनी थकान छिपाकर उनके भविष्य की नींव रखता है। वह अपने जीवन का हर संघर्ष इस विश्वास के साथ करता है कि बुढ़ापे में उसके अपने ही उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन यदि वही संतान अंतिम समय में केवल ऑनलाइन पैसे भेजकर अपना दायित्व पूरा समझने लगे,तो इससे अधिक पीड़ादायक विडंबना क्या हो सकती है? यहाँ यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि किसी भी घटना के पीछे ऐसे कारण हो सकते हैं जो सार्वजनिक रूप से ज्ञात न हों। पारिवारिक संबंध जटिल हो सकते हैं,परिस्थितियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए किसी समाचार के आधार पर किसी व्यक्ति या परिवार का अंतिम नैतिक निर्णय देना उचित नहीं होगा। लेकिन इस घटना ने जिस सामाजिक प्रश्न को जन्म दिया है,वह

अत्यंत गंभीर है-क्या हम धीरे-धीरे रिश्तों को भावनाओं से नहीं, बल्कि लेन-देन से मापने लगे हैं?

आज की शिक्षा हमें सफल पेशेवर तो बना रही है,लेकिन क्या वह हमें अच्छा बेटा,अच्छी बेटी और अच्छा इंसान भी बना रही है? डिग्रियाँ बढ़ रही हैं,लेकिन संस्कार सिकुड़ते जा रहे हैं। करियर की ऊँचाइयाँ छूने की दौड़ में परिवार पीछे छूट रहा है। माता-पिता अब जीवन के केंद्र में नहीं,बल्कि समय मिलने पर याद करने योग्य सूची में शामिल होते जा रहे हैं।

वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या भी इसी बदलते समाज की कहानी कहती है। कभी वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए होते थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता था। आज वहाँ ऐसे माता-पिता भी पहुँच रहे हैं जिनके बच्चे प्रतिष्ठित नौकरियों में हैं, विदेशों में रहते हैं,आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि गरीबी बढ़ी है; इसका अर्थ यह है कि भावनात्मक गरीबी बढ़ी है।

हम यह भी भूलते जा रहे हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। यदि आज कोई अपनी वृद्ध माँ या पिता की उपेक्षा करता है,तो वह अनजाने में अपनी अगली पीढ़ी को भी यही पाठ पढ़ा रहा है। समय का चक्र बड़ा न्यायप्रिय होता है। जो व्यवहार हम अपने माता-पिता के साथ करते हैं,वही किसी न किसी रूप में हमारे सामने लौटकर आता है।

भारतीय संस्कृति में माता-पिता को देवतुल्य माना गया है। यह केवल धार्मिक वाक्य नहीं,बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। माता-पिता के प्रति सम्मान केवल उनके जीवित रहने तक सीमित नहीं होता;उनकी अंतिम यात्रा में कंधा देना भी हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा पुत्रधर्म और पुत्रीधर्म माना गया है। अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं,बल्कि जीवनभर के ऋण के प्रति कृतज्ञता का अंतिम प्रणाम है। इसे किसी वीडियो कॉल या ऑनलाइन भुगतान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।

यहाँ हम किसी एक परिवार की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहें बल्कि यह पूरे समाज को आईना दिखाने का प्रयास है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए–क्या हम भी कहीं अपने माता-पिता को केवल आर्थिक सहायता देकर अपने दायित्व की इतिश्री तो नहीं मान बैठे? क्या हमने कभी उनके साथ बैठकर बिना किसी स्वार्थ के समय बिताया? क्या हमने उनके अकेलेपन को समझने का प्रयास किया? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि धन,पद,प्रतिष्ठा और सफलता सब यहीं रह जाते हैं। अंत में याद रहती है तो केवल इंसानियत और रिश्तों की गर्माहट। जिस दिन माता-पिता इस दुनिया से विदा हो जाते हैं,उस दिन पछतावे के आँसू उन्हें वापस नहीं ला सकते। इसलिए जब तक वे हमारे बीच हैं,उनके साथ समय बिताइए,उनका सम्मान कीजिए,उनकी बातें सुनिए और उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं।

क्योंकि जिस दिन किसी पिता की चिता के सामने उसकी संतान की जगह केवल मोबाइल की स्क्रीन दिखाई देने लगेगी,उस दिन यह समझ लेना चाहिए कि तकनीक जीत गई है,लेकिन इंसान हार गया है। विकास की चमक ने संवेदनाओं की लौ को ढक दिया है, और यदि हमने समय रहते इसे नहीं संभाला, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें आधुनिक तो कहेंगी, लेकिन मानवीय नहीं।

हमें यह ध्यान रखना होगा कि माता-पिता को जीवन भर आपके पैसों की नहीं,आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। उनकी अंतिम यात्रा में दो कदम साथ चलना किसी पर उपकार नहीं, बल्कि उस ऋण का छोटा-सा प्रतिदान है जिसे कोई संतान जीवन भर भी नहीं चुका सकती।

गाँव की हर चीज़ चाहिए, लेकिन गाँव नहीं चाहिए

-डॉ. प्रियंका सौरभ,हिसार,हरियाणा-

गाँव की हर चीज़ चाहिए,लेकिन गाँव नहीं चाहिए। यह एक साधारण-सा वाक्य नहीं,बल्कि आधुनिक भारतीय समाज की बदलती मानसिकता का सटीक चित्रण है। हम गाँव के शुद्ध दूध की बात करते हैं,देसी घी की प्रशंसा करते हैं,जैविक अनाज खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं,गाँव के फलों और सब्जियों को स्वास्थ्य का आधार मानते हैं,गाँव की संस्कृति,लोकगीत,लोकनृत्य और पारंपरिक जीवन को अपनी पहचान बताते हैं,लेकिन जब स्वयं गाँव में रहने की बात आती है तो अधिकांश लोग उससे दूरी बनाना चाहते हैं। यह विरोधाभास केवल जीवन-शैली का नहीं, बल्कि विकास की हमारी अवधारणा का भी प्रश्न है।

भारत को सदियों से गाँवों का देश कहा जाता रहा है। आज भी देश की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव कृषि पर टिकी है और कृषि गाँवों के बिना संभव नहीं। फिर भी विडंबना यह है कि गाँव का उत्पाद सम्मान पाता है,लेकिन गाँव स्वयं उपेक्षा का शिकार है। हम गाँव से सब कुछ लेना चाहते हैं,पर गाँव को वह सम्मान,सुविधाएँ और अवसर देने में पीछे रह जाते हैं जिनका वह अधिकारी है।

आज शहरों में ऑर्गेनिक का बड़ा बाज़ार है। गाँव का गेहूँ,बाजरा,सरसों का तेल,देसी दालें और ताज़ी सब्जियाँ ऊँचे दामों पर बिकती हैं। लोग गाँव के शहद, देसी गुड़ और मोटे अनाज को स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं। लेकिन इन उत्पादों को पैदा करने वाले किसान का जीवन अक्सर संघर्षों से भरा रहता है। जिस किसान की मेहनत शहर के लोगों की थाली सजाती है,उसी किसान के बच्चे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहरों की ओर पलायन करने को विवश हैं।

ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी पूँजी उसके सामाजिक संबंध रहे हैं। सुख-दुःख में पूरा गाँव एक परिवार की तरह खड़ा होता था। विवाह,त्योहार,फसल कटाई या किसी संकट की घड़ी–हर अवसर सामूहिकता का प्रतीक होता था। आज शहरी जीवन में लोग इसी अपनत्व की तलाश करते हैं। बड़े-बड़े अपार्टमेंटों में रहने वाले लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते। दूसरी ओर गाँव की चौपाल, पीपल की छाँव और सामूहिक संवाद अब धीरे-धीरे स्मृतियों में बदलते जा रहे हैं। हम उस आत्मीयता की प्रशंसा तो करते हैं,लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करते।

शिक्षा और रोजगार की तलाश ने गाँवों से युवाओं का पलायन तेज़ किया है। यह पलायन केवल आर्थिक नहीं,सांस्कृतिक भी है। पढ़ा-लिखा युवा शहर में बसना अपनी सफलता मानने लगा है। गाँव लौटना उसे पिछड़ेपन का प्रतीक लगता है। परिणामस्वरूप गाँवों में बुज़ुर्ग,महिलाएँ और बच्चे अधिक रह गए हैं, जबकि युवाओं की ऊर्जा शहरों में खप रही है। यदि गाँवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ,उद्योग और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध हों,तो बड़ी संख्या में लोग अपने गाँव में ही रहना पसंद करेंगे।

यह भी सच है कि गाँवों में अनेक चुनौतियाँ हैं। शिक्षा,स्वास्थ्य,परिवहन,इंटरनेट, पेयजल,स्वच्छता और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी आज भी कई क्षेत्रों में दिखाई देती है। सामाजिक कुरीतियाँ,जातिगत भेदभाव और रूढ़िवादिता जैसी समस्याएँ भी मौजूद हैं। इन कमियों को स्वीकार करना आवश्यक है,लेकिन समाधान गाँव से भागने में नहीं,बल्कि गाँव को बेहतर बनाने में है।

आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब गाँव का महत्व और बढ़ जाता है। स्वच्छ हवा,खुले मैदान,पेड़-पौधे,जल स्रोत और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन गाँव की पहचान हैं। शहरों में कृत्रिम पार्क बनाकर लोग प्रकृति का अनुभव करना चाहते हैं,जबकि गाँव में प्रकृति जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यदि हमने गाँवों को बचाए बिना केवल शहरों का विस्तार किया,तो आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक जीवन केवल पुस्तकों और चित्रों में देखने को मिलेगा।

कोविड-19 महामारी ने भी हमें गाँव का महत्व समझाया। जब शहरों की आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हो गईं,तब लाखों लोग अपने गाँव लौटे। गाँव ने उन्हें आश्रय दिया, भोजन दिया और जीवन को फिर से संभालने का अवसर दिया। उस समय यह स्पष्ट हो गया कि गाँव केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं,बल्कि संकट के समय समाज की सबसे मजबूत सुरक्षा-व्यवस्था भी है।

आज आवश्यकता केवल ग्रामीण विकास योजनाएँ बनाने की नहीं, बल्कि विकास की सोच बदलने की है। गाँव को शहर बनाने की नहीं,बल्कि गाँव को उसकी विशेषताओं के साथ आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की आवश्यकता है। अच्छी सड़कें,गुणवत्तापूर्ण विद्यालय,डिजिटल कनेक्टिविटी,आधुनिक अस्पताल,कृषि आधारित उद्योग,कौशल विकास और स्थानीय रोजगार–ये सब गाँव के विकास की वास्तविक आधारशिला हैं। यदि अवसर गाँव में होंगे तो पलायन स्वतः कम होगा।

हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी गाँव के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना होगा। बच्चों को यह समझाना होगा कि खेती केवल एक पेशा नहीं,बल्कि राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा का आधार है। किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षक भी है। गाँव केवल रहने की जगह नहीं,बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल स्रोत है। मीडिया और मनोरंजन जगत की भी इसमें बड़ी भूमिका है। अक्सर गाँव को या तो अत्यधिक पिछड़ा दिखाया जाता है या केवल रोमांटिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

रवींद्रनाथ टैगोर : विचारों का वह वृक्ष,जिसकी छाया आज भी शीतल है...

सभ्यताएँ अपनी सबसे बड़ी पूँजी स्मारकों में नहीं, उन विचारों में बचाकर रखती हैं जो पीढ़ियों का हाथ थामे रहते हैं। 7 अगस्त 1941 को रवींद्रनाथ टैगोर का शरीर कोलकाता के जोड़ासाँको में शांत हुआ,पर उनका सृजन और चिंतन पहले से अधिक जीवित हो उठा। उनका प्रस्थान किसी अध्याय का अंत नहीं,नई दिशाओं में खुलते एक विराट संवाद की शुरुआत था। आज भी किसी वृक्ष तले बैठा बालक जब कल्पना का पहला शब्द गढ़ता है,या शहरी कोलाहल में कोई मन पक्षियों का स्वर सुन लेता है,तब टैगोर हमारे बीच उपस्थित हो उठते हैं। उनकी पुण्यतिथि स्मरण का अनुष्ठान नहीं,आत्ममंथन का क्षण है—क्या हमने अब भी अपने भीतर संवेदना,सौंदर्य और प्रकाश की वह ज्योति बचा रखी है,जिसे उन्होंने अपने जीवन और साहित्य से प्रज्वलित किया था...

कृति आर.के.जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

विचार तभी साँस लेते हैं,जब वे परंपरा का सम्मान करते हुए उसकी सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस रखें। जोड़ासाँको ने रवींद्रनाथ टैगोर को संस्कार, कला, संगीत और उदार विचारों का वातावरण दिया,पर किसी मान्यता को अंतिम सत्य मानना नहीं सिखाया। विद्यालय की बंधी व्यवस्था उन्हें रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने ज्ञान को पुस्तकों से निकालकर प्रकृति में खोजा। वृक्ष, ऋतुएँ और आकाश उनके शिक्षक थे। यही सोच शांतिनिकेतन बनी,जहाँ शिक्षा का उद्देश्य सूचना जुटाना नहीं, भीतर के मनुष्य को जगाना था। वहाँ परीक्षा से ज्यादा जीवन का अनुभव महत्त्व रखता था। इसलिए शांतिनिकेतन केवल शिक्षण संस्थान नहीं,ऐसी दृष्टि बना,जिसमें ज्ञान और संवेदना एक-दूसरे के पूरक बने।

भाषा की सबसे बड़ी सफलता सीमाएँ लाँघकर मनुष्य से मनुष्य को जोड़ना है। गीतांजलि का नोबेल सम्मान रवींद्रनाथ टैगोर का निजी गौरव नहीं,एशिया की सांस्कृतिक चेतना की वैश्विक स्वीकृति था। उनकी कविता का ईश्वर मंदिरों में नहीं,मनुष्य के निर्मल अंतर्मन में बसता है। इसलिए उनकी रचनाएँ भय नहीं,आत्मविश्वास और भीतरी स्वतंत्रता जगाती हैं। गोरा,घरे-बाइरे और काबुलीवाला उपदेश नहीं देते; वे समाज के अंतर्विरोध खोलकर पाठक को स्वयं से प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके लिए साहित्य मनोरंजन नहीं,आत्मपहचान का माध्यम था,जहाँ मनुष्य स्वयं से साक्षात्कार करता है। राष्ट्र का सबसे ऊँचा स्वर वह है, जिसमें विवेक, करुणा और आत्मसम्मान साथ बोलते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर का देशप्रेम इसी आधार पर खड़ा था। जलियाँवाला बाग़ के बाद नाइटहुड लौटाना उनके लिए राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं,आत्मसम्मान का निर्णय था। उन्होंने राष्ट्रवाद को कभी आक्रोश की भाषा नहीं बनने दिया। एकला चलो रे भीड़ से अलग होने का नहीं, सत्य के लिए अकेले डटे रहने का संदेश है। उनका विश्वास था कि बाहरी स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता के बिना अधूरी है। इसलिए हिंसा उन्हें किसी आदर्श का स्थायी मार्ग नहीं लगी। आज, जब राष्ट्रप्रेम कई बार शोर और कटुता में सिमट जाता है,टैगोर याद दिलाते हैं कि प्रेम से रिक्त देशभक्ति अंततः अपना अर्थ खो देती है।

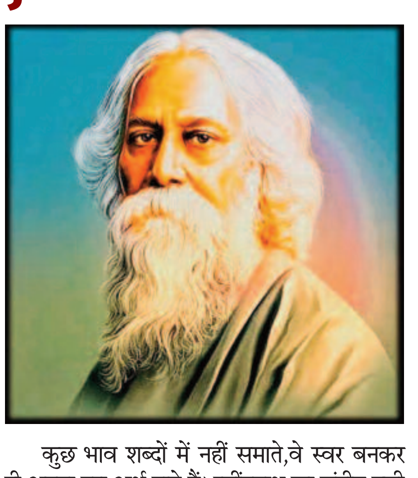

कुछ भाव शब्दों में नहीं समाते,वे स्वर बनकर ही अपना पूरा अर्थ पाते हैं। रवींद्रनाथ का संगीत उसी अनुभूति का विस्तार है। रवींद्र संगीत में प्रकृति पृष्ठभूमि नहीं,मनुष्य के भावों की सहभागी है। हवा, नदी,वर्षा, संध्या और बदलती ऋतुएँ प्रेम,विरह और आशा के साथ एकाकार हो उठती हैं। जन गण मन और आमार सोनार बांग्ला सिद्ध करते हैं कि सच्ची कला सीमाओं और राजनीति से कहीं बड़ी होती है। टैगोर के लिए संगीत साधना था,जहाँ गायक और श्रोता एक ही लय में अपना अहं विसर्जित कर देते हैं। इसलिए उनके गीत समय के साथ पुराने नहीं होते; वे मनुष्य के शाश्वत अनुभवों से जन्मे हैं।

सृजन का स्वभाव एक ही भाषा में ठहरना नहीं जानता। जीवन के उत्तरार्ध में रवींद्रनाथ टैगोर ने शब्दों से आगे बढ़कर रंग और रेखाओं में अपनी अनुभूतियाँ उकेरीं। चित्रकला उनके लिए परंपरा की पुनरावृत्ति नहीं,आत्म-अन्वेषण का नया माध्यम बनी। लोक और आदिवासी कला की प्रेरणा को उन्होंने अपनी मौलिक दृष्टि से ऐसा रूप दिया कि अमूर्त आकृतियाँ भी गहरे भाव व्यक्त करने लगीं। उनकी तूलिका मानो कविता की ही दूसरी अभिव्यक्ति थी। इससे स्पष्ट हुआ कि प्रतिभा किसी एक विधा की सीमाओं में नहीं बँधती। कवि,कथाकार, संगीतकार, चित्रकार और शिक्षाविद्–हर रूप में वही जिज्ञासु चेतना सक्रिय रही, जो जीवन के अनदेखे अर्थों की निरंतर तलाश करती रही।

हर युग अपनी सबसे बड़ी कीमत किसी न किसी रूप में चुकाता है। हमारे समय ने सुविधा पाई है, पर संवेदना का कुछ हिस्सा खो दिया है। तकनीक ने गति दी, किंतु प्रकृति और अपने भीतर के मनुष्य से दूरी भी बढ़ाई। ऐसे दौर में रवींद्रनाथ टैगोर का चिंतन नई रोशनी देता है। उनकी शिक्षा-दृष्टि बताती है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल दक्षता नहीं,व्यक्तित्व का परिष्कार भी है। विश्वभारती इसी विचार का साकार रूप है, जहाँ शिक्षा जीवन,संस्कृति और प्रकृति से जुड़ती है। उनके लिए सौंदर्य और सत्य अलग नहीं,एक ही अनुभूति के दो आयाम थे। इसलिए उनका संदेश आज भी हमें ठहरने,स्वयं से मिलने,प्रकृति से जुड़ने और मनुष्यता को जीवन का केंद्र बनाने की प्रेरणा देता है।

किसी महान जीवन का सबसे विश्वसनीय प्रमाण उसकी छोड़ी हुई विरासत नहीं,उसकी बची हुई प्रासंगिकता होती है। इसलिए 7 अगस्त केवल स्मरण का दिन नहीं, आत्मपरीक्षण का अवसर है। रवींद्रनाथ टैगोर को सचमुच याद करना है, तो उनके शब्दों का नहीं, उनके विचारों का आचरण करना होगा। प्रकृति के प्रति सम्मान,शिक्षा में स्वतंत्रता,कला में मानवीयता और राष्ट्रप्रेम में करुणा—यही उनकी सबसे बड़ी धरोहर है। उनका प्रकाश आज भी हमारे भीतर पहुँच सकता है,यदि हम उसके लिए स्थान बचाए रखें। किसी कवि की सच्ची श्रद्धांजलि पुष्प नहीं वह जीवन है जो उसके स्वप्नों को आगे बढ़ाए। तभी टैगोर इतिहास की स्मृति नहीं,हमारे समय की आवश्यकता बने रहेंगे।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

10 दिन की तलाश के बाद पटना से दबोचा गया नाबालिग दुष्कर्म का आरोपी,गिरफ्तारी से पहले गरमाई थी सियासत

- भाजपा ने एसपी को सौंपा था ज्ञापन,कांग्रेस पर समझौते का दबाव बनाने के लगाए थे आरोप,पुलिस ने बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर लिया आरोपी
- देवघर,वासुकीनाथ,पुरी और रांची तक तलाश के बाद पटना में मिली सफलता,मोबाइल बंद कर लगातार बदल रहा था ठिकाना...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के बहुचर्चित नाबालिग आदिवासी बालिका से कथित दुष्कर्म मामले में आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी तरुण कुमार जायसवाल को विशेष पुलिस टीम ने करीब 10 दिनों तक लगातार विभिन्न राज्यों में तलाश करने के बाद बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस अंबिकापुर ला रही है। आरोपी की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है,जब पिछले दो दिनों से यह मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से सुर्खियों में था तथा गिरफ्तारी में देरी को लेकर भाजपा ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।

गिरफ्तारी से पहले सड़क से लेकर एसपी कार्यालय तक गूंजा था मामला

आरोपी की गिरफ्तारी से पहले भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा और महिला मोर्चा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया था। भाजपा नेताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सुरक्षा तथा मामले को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा था कि नाबालिग आदिवासी बालिका से जुड़ा यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और आरोपी की गिरफ्तारी में देरी से लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो रहा है।

पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने के लगाए गए थे आरोप

भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी पक्ष के लोग लगातार पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के परसा मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच विवेक पैकरा तथा उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर कथित रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर समझौते का प्रयास करने का आरोप लगाया था। भाजपा ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की थी। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष बिंदेश्वरी पैकरा ने कहा था कि आरोपी प्रभावशाली होने के कारण अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है,इसलिए उसकी शीघ्र गिरफ्तारी आवश्यक है। वहीं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़े ने ग्राम भफौली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा था कि महिला मोर्चा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा।

एसएसपी ने बनाई थीं दो विशेष टीमें,घोषित किया था इनाम

पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 504/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराओं 4 एवं 6 के तहत मामला दर्ज है। घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार था। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति के लिए 5 हजार रुपये के इनाम की भी घोषणा की गई थी।

मोबाइल बंद,राहगीरों के फोन से करता था संपर्क : पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लगातार अपना मोबाइल बंद रख रहा था और पहचान छिपाने के लिए लगातार शहर बदल रहा था। वह जरूरत पड़ने पर राह चलते लोगों से मोबाइल लेकर अपने परिचितों से संपर्क करता था,जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पुलिस टीम ने आरोपी के बैंक खाते फ्रीज कराए,यात्रा संबंधी जानकारी जुटाई, संदिग्ध मोबाइल नंबरों की तकनीकी निगरानी की और रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ की। इसी दौरान पुलिस को उसके अलग-अलग राज्यों में छिपे होने के संकेत मिले।

देवघर से पुरी,रांची होते हुए पटना पहुंचा आरोपी : विशेष पुलिस टीम आरोपी की तलाश में झारखंड और ओडिशा के कई शहरों तक पहुंची। पुलिस ने देवघर,वासुकीनाथ,पुरी और रांची में संभावित ठिकानों पर दबिश दी। लगातार तकनीकी निगरानी और मानवीय सूचना तंत्र के आधार पर आखिरकार आरोपी का लोकेशन बिहार की राजधानी पटना में मिला। इसके बाद पटना पुलिस के सहयोग से आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसे स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया, जिसके बाद पुलिस उसे अंबिकापुर लेकर रवाना हुई।

लाइसेंसी 12 बोर बंदूक भी जब्त : पुलिस ने बताया कि आरोपी के नाम से जारी 12 बोर डीबीबीएल लाइसेंसी बंदूक का लाइसेंस निरस्त किए जाने के बाद उसके घर से हथियार और लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। मामले में अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और विवेचना जारी है।

अब आगे क्या? आरोपी को अंबिकापुर लाने के बाद पुलिस उससे विस्तृत पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियां घटना से जुड़े सभी तथ्यों, फरारी के दौरान उसकी गतिविधियों तथा संभावित सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं। यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने आरोपी को शरण दी,साक्ष्य छिपाने में मदद की या न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

घटनाक्रम एक नजर में...

- नाबालिग आदिवासी बालिका से कथित दुष्कर्म का मामला दर्ज।
- घटना के बाद आरोपी तरुण जायसवाल फरार हो गया।
- डीआईजी-एसएसपी ने दो विशेष टीमों का गठन कर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया।
- भाजपा ने गिरफ्तारी में देरी पर एसपी को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया।
- पीड़ित परिवार पर समझौते का दबाव बनाने के आरोप भी सामने आए।
- पुलिस ने 10 दिन तक कई राज्यों में तलाश के बाद आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया।
- ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को अंबिकापुर लाया जा रहा है।

भाजपा विधि प्रकोष्ठ का फैसला : आरोपी की पैरवी नहीं करेंगे अधिवक्ता

नाबालिग आदिवासी बालिका से कथित दुष्कर्म के मामले में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिवक्ता आरोपी की ओर से अदालत में पैरवी नहीं करेंगे। प्रकोष्ठ का कहना है कि यह फैसला मामले की गंभीरता,पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता और आदिवासी समाज की गरिमा के सम्मान को ध्यान में रखकर लिया गया है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने कहा कि नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। ऐसे मामलों में संगठन पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ा है तथा दोषियों को कानून के अनुसार कठोरतम सजा दिलाने की दिशा में हरसंभव प्रयास का समर्थन करेगा। प्रकोष्ठ ने कहा कि न्याय की स्थापना और पीड़ित पक्ष के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग,एमबीबीएस इंटर्न की अनिश्चितकालीन हड़ताल

15,900 रुपए मासिक स्टाइपेंड को बताया बेहद कम,प्रदेशभर में समान मानदेय की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने और प्रदेशभर में समान मानदेय लागू करने की मांग को लेकर अधिष्ठाता (डीन) को ज्ञापन सौंपते हुए हड़ताल की घोषणा की है। ज्ञापन में इंटर्न डॉक्टरों ने कहा है कि वर्तमान में उन्हें प्रतिमाह 15,900 रुपए स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न को 24,240 से 36,360 रुपए तक मानदेय मिल रहा है। पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में भी एमबीबीएस इंटर्न को करीब 30 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिए जाने का

उल्लेख किया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में समान और उचित स्टाइपेंड लागू करने की मांग की गई है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पहले भी कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और कार्यभार को देखते हुए वर्तमान स्टाइपेंड पर्याप्त नहीं है। इसे लेकर 7 अगस्त से सभी एमबीबीएस इंटर्न अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अस्पताल परिसर में एमबीबीएस इंटर्न ने प्रदर्शन किया अपनी मांगे रखी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि हड़ताल का उद्देश्य मरीजों को परेशान करना नहीं,बल्कि अपनी लंबे समय से लंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है।

दो घंटे के ऑपरेशन से डेढ़ साल के मासूम की बची जान,समय पर सर्जरी से टली अंतड़ी सड़ने की नौबत

ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया से फंसी थी छोटी और बड़ी आंत,मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल सर्जरी कर बचाई जिंदगी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे डेढ़ वर्षीय मासूम की जान मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने समय रहते सफल ऑपरेशन कर बचा ली। करीब दो घंटे तक चली सर्जरी में डॉक्टरों ने बच्चे की फंसी हुई छोटी और बड़ी आंत को सुरक्षित निकालकर उसके सही स्थान पर स्थापित किया। डॉक्टरों के अनुसार यदि समय पर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो आंत की रक्त आपूर्ति रुकने से वह सड़ने लगती और बच्चे की जान बचाना बेहद मुश्किल हो सकता था। जानकारी के अनुसार,सूरजपुर जिले के डेढ़ वर्षीय रूपेंद्रनाथ को 23 जुलाई को अचानक पेट फूलने और तेज दर्द की शिकायत हुई। परिजन उसे जिला अस्पताल सूरजपुर लेकर पहुंचे, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर 29 जुलाई को अंबिकापुर स्थित राजमोहिनी देवी शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल

रेफर किया गया। यहां जांच के दौरान सोनोग्राफी में पता चला कि बच्चे की आंत पेट के निचले हिस्से में फंस गई है। डॉक्टरों ने इसे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बताया और स्थिति गंभीर देखते हुए उसी दिन तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया। करीब दो घंटे चली सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि बच्चे की छोटी और बड़ी दोनों आंत फंस गई थीं। अत्यंत सावधानी से उन्हें बाहर निकालकर उनके सामान्य स्थान पर स्थापित किया गया। सफल ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत में तेजी से सुधार हुआ और स्वस्थ होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

समय पर इलाज से बची जान : डॉक्टरों ने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में यदि समय पर उपचार नहीं मिले तो फंसी हुई आंत तक रक्त का प्रवाह बंद हो सकता है। इससे आंत सड़ने (गैंग्रीन) का खतरा बढ़ जाता है और मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए पेट में असामान्य सूजन,तेज दर्द, उल्टी या हर्निया की सूजन अचानक सख्त होने जैसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी है।

इन डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन : इस सफल सर्जरी में शिशु शल्य चिकित्सक डॉ. पी.आर. शिवहरे, डॉ. मनोज भारती, डॉ. शुभम कांत तथा एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. रूपक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टरों की टीम की सतर्कता और समय पर किए गए ऑपरेशन से मासूम की जान बच गई।

तेज रफ्तार बस ने इनोवा को मारी टक्कर,महिला की मौत,छह घायल

बिलासपुर से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार,एक की हालत गंभीर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर गुरुवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के

अनुसार, घटना बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात करीब 12.30 बजे की है। लमगांव निवासी आसन लाल तिग्गा, दिलीप कुमारी तिग्गा और उनके रिश्तेदार बिलासपुर में एक परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल होकर इनोवा वाहन (सीजी 15 ईडी 9050) से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान लखनपुर क्षेत्र में रम्पुरहीन माता मंदिर और राजवाड़े ढाबा के बीच सामने से आ रही पॉपुलर बस (सीजी 15 डीएम 0186) ने कथित रूप से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए इनोवा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इनोवा के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दिलीप कुमारी तिग्गा के सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों के सीने, सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं।

भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पहुंचाई मदद : हादसे के समय रायपुर से लौट रहे लखनपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश बारी ने घटनास्थल पर रुककर घायलों को एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर पहुंचाने में मदद की। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1), 281 एवं 125(ए) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हाईवे किनारे ढाबों के सामने बेतरतीब ढंग से खड़े भारी वाहनों और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।

आलोक दुबे की शिकायत पर करोड़ों की जमीन फर्जीवाड़े का मामला दर्ज,मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर कराई गई थी रजिस्ट्री

1962 में मृत नोहर साय के नाम की जमीन बेचने का आरोप,पांच आरोपी नामजद...भाजपा नेता ने विशेष जांच दल गठित करने की उठाई मांग...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

शहर में जमीन फर्जीवाड़े के एक बड़े मामले में कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पार्षद आलोक दुबे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। मामले में आरोप है कि वर्ष 1962 में मृत हो चुके व्यक्ति के नाम दर्ज भूमि की रजिस्ट्री उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर, कूटरचित दस्तावेज और फर्जी पहचान पत्र के माध्यम से कराई गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घुटरापारा, अम्बिकापुर स्थित खसरा क्रमांक 356/2, रकबा 0.065 हेक्टेयर भूमि

राजस्व रिकॉर्ड में मृतक नोहर साय रजवाड़े के नाम दर्ज थी,जिनकी मृत्यु वर्ष 1962 में हो चुकी थी। जांच में प्रथम दृष्टया सामने आया कि सितंबर 2025 में मैनपाट निवासी अमर सिंह को नोहर साय बताकर उसकी फर्जी पहचान बनाई गई। आरोप है कि आधार कार्ड में कूटरचना कर मृतक के नाम से पहचान पत्र तैयार किया गया और उसी के आधार पर पंजीयन कार्यालय में विक्रय विलेख निष्पादित कराया गया। जांच में यह भी सामने आया कि भूमि की पहली रजिस्ट्री के बाद मार्च 2026 में उक्त जमीन लगभग 30 लाख रुपये में अन्य लोगों को बेच दी गई। पुलिस का आरोप है कि इस लेन-देन से प्राप्त राशि आरोपियों के बीच बांटी गई और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया गया। कोतवाली पुलिस ने अमर सिंह उर्फ नोहर साय रजवाड़े, पायल पटेल, वर्षा पटेल,रामनिवास गुप्ता उर्फ बोखा तथा बंटी पटेल उर्फ वर्षित पटेल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

आलोक दुबे बोले...यह अकेला मामला नहीं,सैकड़ों जमीनों की हो विशेष जांच : शिकायतकर्ता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता आलोक दुबे ने दावा किया कि यह केवल एक भूमि का मामला नहीं है। उनके अनुसार नवागढ़, श्रीगढ़, कांतीप्रकाशपुर, मानिकप्रकाशपुर, लालमाटी, पुरा और दरिमा रोड सहित कई क्षेत्रों में सैकड़ों एकड़ शासकीय एवं निजी भूमि के रिकॉर्ड में कथित कूटरचना कर बड़े पैमाने पर फर्जी रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकार अभिलेखों में छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपये की जमीन का बंदरबांट किया गया है। आलोक दुबे ने कलेक्टर सरगुजा से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि व्यापक जांच कराई जाए तो ऐसे सैकड़ों प्रकरण सामने आ सकते हैं और भूमाफियाओं के संगठित नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

सडक़ बनी खेत, ग्रामीणों ने रोपा धान,वीडियो वायरल

जर्जर सडक़ से परेशान ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन, बोले...एंबुलेंस तक नहीं पहुंचती गांव....

-संवाददाता-
लुण्ड्रा,06 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

लुण्ड्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत उदारी के बैरापारा स्थित अटल चौक के पास ग्रामीणों ने जर्जर सडक़ के विरोध में सडक़ पर ही धान की रोपाई कर अनोखा प्रदर्शन किया। गुरुवार दोपहर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से सडक़ निर्माण की मांग की जा रही है। सरपंच, सचिव और जनप्रतिनिधियों को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक सडक़ नहीं बन सकी। बारिश के दौरान सडक़ पूरी

तरह कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे आवागमन बाधित रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि खराब सडक़ के कारण गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंच पाती। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक प्रबोध मिंज को भी कई बार समस्या बताई गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। आक्रोशत ग्रामीणों ने सडक़ पर धान की रोपाई कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और जल्द सडक़ निर्माण की मांग की।

सरगुजा सेक्टर की अंतरमहाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर तय करने पर मंथन

अंबिकापुर में 28 कॉलेजों के प्राचार्य व क्रीड़ा अधिकारियों की बैठक, निष्पक्ष और समयबद्ध आयोजन पर जोर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभाकक्ष में गुरुवार को सरगुजा सेक्टर के अंतर्गत आने वाले शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों और क्रीड़ा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार सिन्हा ने की। बैठक में सरगुजा,बलरामपुर और जशपुर जिले के 28 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के क्रीड़ा अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 2026-27 की अंतरमहाविद्यालयीन खेल-कूद प्रतियोगिताओं के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन की रूपरेखा तैयार

करना था। बैठक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की तिथियों का निर्धारण, मेजबान महाविद्यालयों का चयन, खिलाड़ियों के पंजीयन,चयन प्रक्रिया, प्रतियोगिता नियमावली के पालन, सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रशासनिक एवं तकनीकी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार सिन्हा ने सभी क्रीड़ा अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतियोगिताओं का आयोजन निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

इनके माध्यम से अनुशासन,नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है। बैठक में उपस्थित सभी क्रीड़ा अधिकारियों ने प्रतियोगिताओं के सफल संचालन के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

C M Y K

आईसी मार्ट प्रकरण : हाईकोर्ट ने कोरिया एसपी को किया तलब,पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोपों का लिया संज्ञान

जगत बैद और अधिवक्ता दीपक बैद की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित,21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

न्यायालय ने कहा...एफआईआर दर्ज होने से पहले अभियोजन के पास उपलब्ध तथ्यों और जानकारी के साथ एसपी हों उपस्थित

-संवाददाता-
बिलासपुर/बैकुंठपुर 06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बहुचर्चित आईसी मार्ट व नाबालिक छात्रा आत्महत्या प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, न्यायालय ने यह निर्देश पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर लगाए गए गंभीर आरोपों का संज्ञान लेने के बाद दिया है, यह आदेश न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने 5 अगस्त 2026 को पारित किया, न्यायालय के समक्ष आईसी मार्ट प्रकरण में आरोपी बनाए गए जगत बैद और अधिवक्ता दीपक बैद द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद न्यायालय ने तत्काल कोई निर्णय नहीं सुनाया और आदेश सुरक्षित रखते हुए मामले को 21 अगस्त 2026 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

एसपी को किया तलब-हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, न्यायालय ने उन्हें विकल्प दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों,अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें।

एफआईआर से पहले क्या थे तथ्य? कोर्ट ने मांगी जानकारी-हाईकोर्ट ने एसपी को निर्देश दिया है कि वे न्यायालय को यह जानकारी उपलब्ध कराएं कि एफआईआर दर्ज किए जाने से पहले अभियोजन के पास कौन-कौन से तथ्य और सामग्री उपलब्ध थी,आदेश में कहा गया है कि एसपी अभियोजन द्वारा एफआईआर दर्ज करने से पूर्व संकलित की गई जानकारी और तथ्यों के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, यह निर्देश इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि न्यायालय ने सीधे एफआईआर के पूर्व उपलब्ध तथ्यों के संबंध में जानकारी मांगी है।

दो अग्रिम जमानत याचिकाओं पर हुई संयुक्त सुनवाई...

हाईकोर्ट के आदेश पत्र के अनुसार CRA No. 1795/2026 तथा CRA No. 1800/2026 पर एक साथ सुनवाई की गई,याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा,जबकि राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए।

पीड़िता के पिता ने जताई जमानत पर आपत्ति

आदेश पत्र में उल्लेख है कि न्यायालय के पूर्व निर्देश के पालन में पीड़िता के पिता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए, उन्होंने आरोपियों को अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पीड़ित पक्ष की आपत्ति को रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है।

पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोपों का उल्लेख

सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष पुलिस प्रशासन के कार्य निष्पादन को लेकर गंभीर आरोप रखे गए, आदेश पत्र में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि- 'Serious allegation against the functioning of the Police administration has been lodged...'अर्थात न्यायालय के समक्ष पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के संबंध में गंभीर आरोप लगाए गए हैं,यद्यपि आदेश पत्र में इन आरोपों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है,लेकिन इन्हीं आरोपों के मद्देनज़र न्यायालय ने आगे का महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया।

21 अगस्त को फिर होगी सुनवाई...

हाईकोर्ट ने मामले को 21 अगस्त 2026 के लिए सूचीबद्ध किया है, उस दिन— एसपी कोरिया न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे,न्यायालय के समक्ष मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की जाएगी,साथ ही जगत बैद एवं अधिवक्ता दीपक बैद की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी आदेश आने की संभावना है, हालांकि अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा उसी दिन पारित किया जाएगा या नहीं, यह न्यायालय की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

मामले की पृष्ठभूमि

आईसी मार्ट आत्महत्या प्रकरण में बैकुंठपुर सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज होने के बाद आईसी मार्ट संचालक विनोद बैद, उनके बड़े भाई जगत बैद तथा अधिवक्ता दीपक बैद को आरोपी बनाया गया था, विनोद बैद की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की हैं।

हाईकोर्ट के आदेश का महत्व

5 अगस्त को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने किसी भी पक्ष के आरोपों पर अंतिम टिप्पणी नहीं की है, न्यायालय ने केवल यह दर्ज किया है कि पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन्हीं आरोपों के मद्देनज़र पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज होने से पूर्व उपलब्ध तथ्यों और अभियोजन की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है,अब इस बहुचर्चित प्रकरण में 21 अगस्त 2026 की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उसी दिन एसपी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी आगे की न्यायिक कार्रवाई होने की संभावना है।

फर्जी अंकसूची के सहारे 28 साल नौकरी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर गंभीर आरोप,जांच नहीं हुई तो प्रशासन पर उठेंगे सवाल...

जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और एफआईआर की मांग,शिकायतकर्ता ने उम्र,अंकसूची और शासकीय अभिलेखों में विरोधाभास का लगाया आरोप

-सुदामा राजवाड़े-

वाड्रफनगर (बलरामपुर),06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)

बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटराही खास की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर कथित रूप से फर्जी अंकसूची और गलत जन्मतिथि के आधार पर नौकरी हासिल करने का गंभीर आरोप लगा है। मामले में ग्राम कोटराही निवासी धनराज पण्डो ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच कराने तथा आरोप सही पाए जाने पर आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में दावा किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विद्यावती यादव ने वर्ष 1999 में कथित रूप से फर्जी अंकसूची और गलत जन्मतिथि का उपयोग कर नौकरी प्राप्त की। शिकायतकर्ता के अनुसार नियुक्ति के समय प्रस्तुत दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि 12 मई 1968 दर्ज है, जबकि उपलब्ध अन्य अभिलेख इस जानकारी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

शिकायत में कई दस्तावेजों का हवाला,उम्र को लेकर विरोधाभास का दावा : शिकायतकर्ता का दावा है कि विद्यावती यादव की पहली पुत्री की जन्मतिथि 24 अप्रैल 1975 दर्ज है। यदि यह तथ्य सही है तो नियुक्ति के समय प्रस्तुत जन्मतिथि पर स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होते हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में विद्यावती यादव की आयु 72 वर्ष अंकित है। वहीं वर्ष 2007 के राजस्व अभिलेख में उनकी आयु 52 वर्ष दर्ज बताई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि वर्तमान आयु 72 वर्ष सही है तो वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से लगभग 10 वर्ष अधिक हो चुकी हैं। ऐसे में लंबे समय से सेवा जारी रहने पर भी प्रश्न उठ रहे हैं।

यदि आरोप सही हैं तो यह केवल अनियमितता नहीं,गंभीर अपराध का विषय : मामले में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि किसी सरकारी सेवा में कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गई है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। साथ ही कथित रूप से पिछले 28 वर्षों में प्राप्त शासकीय वेतन-भत्तों की वसूली भी की जाए।

प्रशासनिक जांच अब परीक्षा की घड़ी : यह मामला केवल एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और सरकारी अभिलेखों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप निराधार हैं तो जांच से सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अब निगाहें जिला प्रशासन पर हैं कि वह इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेकर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करता है।

परियोजना अधिकारी से पक्ष नहीं मिल सका

समाचार के संबंध में वाड्रफनगर परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होने के कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

500 करोड़ के एआई मिशन से बदलेगी छत्तीसगढ़ की डिजिटल तस्वीर : भाजपा

भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जताया आभार,कहा...एआई मिशन से सुशासन,कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

भाजपा सरगुजा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन' को दी गई मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के डिजिटल भविष्य के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा...कि यह मिशन सुशासन, नई तकनीक,कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित होगा। भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि राज्य सरकार ने पांच वर्षों की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से इस महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है,बल्कि दूरस्थ जिलों, छोटे शहरों और कस्बों तक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच सुनिश्चित करना है,ताकि अंतिम व्यक्ति तक तकनीक का लाभ पहुंच सके। उन्होंने बताया कि मिशन के अंतर्गत प्रदेशभर में 100 अत्याधुनिक एआई डेटा लैब स्थापित की जाएंगी।

शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के लगभग 6 लाख विद्यार्थियों तथा 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई आधारित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। शासन-प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सरल और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं भी विकसित की जाएंगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से तकनीकी विकास के नाम पर केवल दावे करती रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कंप्यूटरीकरण के सपने की चर्चा तो कांग्रेस लगातार करती है,लेकिन दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद उस दिशा में ठोस पहल नहीं कर सकी। इसके विपरीत भाजपा सरकार ने योजनाओं को धरातल पर उतारकर यह सिद्ध किया है कि डिजिटल परिवर्तन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होता है।

24 हजार वेतन,25 हजार का डीजल! आखिर सभापति रोज जाते कहां थे 114 किलोमीटर?

जनवरी के डीजल बिल ने खड़े किए सवाल,भाजपा नेता कैलाश मिश्रा बोले...'शहर से ज्यादा गाड़ी दौड़ रही है', डीजल खर्च की जांच और एफआईआर की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नगर निगम अम्बिकापुर में डीजल खर्च को लेकर एक बार फिर सवालों की गूंज तेज हो गई है। इस बार निशाने पर नगर निगम के सभापति हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जनवरी 2026 में सभापति के वाहन पर 271 लीटर डीजल की खपत दर्शाई गई, जिस पर 25,609 रुपये खर्च हुए। उनका दावा है कि यह औसतन प्रतिदिन करीब 114 किलोमीटर के सफर के बराबर बैठता है, जबकि सभापति का मासिक वेतन-भत्ता लगभग 24 हजार रुपये है। कैलाश मिश्रा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि लगता है 'शहर से ज्यादा तो गाड़ी दौड़ रही है।' उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अम्बिकापुर नगर निगम का क्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि रोज 114 किलोमीटर का दौरा करना पड़े, या फिर डीजल की खपत के पीछे कोई और कहानी छिपी है?

'शहर चमन हो रहा है या डीजल टैंक?' मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि यदि प्रतिदिन इतना व्यापक भ्रमण वास्तव में हुआ है तो निश्चित ही शहर की हर समस्या समाप्त हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा,'यदि रोज 114 किलोमीटर निरीक्षण हो रहा है तो शहर समस्या मुक्त, चमन और आदर्श बन जाना चाहिए था। आखिर इतनी दौड़-भाग का नतीजा जमीन पर क्यों दिखाई नहीं देता? '

डीजल चोरी या लापरवाही? जांच से खुलेगा राज : भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि नगर निगम में डीजल की खपत और भुगतान की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। यदि अभिलेखों में गड़बड़ी, फर्जी भुगतान या डीजल की कथित हेराफेरी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी धन जनता के टैक्स से आता है और उसकी एक-एक बूंद का हिसाब होना चाहिए। मितव्ययिता का उपदेश जनता को देने वाली व्यवस्था को पहले स्वयं अपने खर्चों का जवाब देना चाहिए।

अब जवाब का इंतजार : डीजल खर्च को लेकर लगाए गए इन आरोपों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है कि वह रिकॉर्ड सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करे और यदि आरोप निराधार हैं तो तथ्यों के साथ उनका खंडन करे। वहीं यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो कार्रवाई भी उतनी ही पारदर्शी होनी चाहिए।

गुरुघासीदास वार्ड में पहले आंगनबाड़ी भवन का शिलान्यास

12 लाख से बनेगा भवन, 3.20 लाख की लागत से नाली मरम्मत कार्य का भी हुआ शुभारंभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नगर निगम के गुरुघासीदास वार्ड में गुरुवार को वार्ड के पहले आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। वार्ड पार्षद शुभम जायसवाल के प्रयासों से बनने वाला यह भवन 12 लाख रुपये की लागत से तैयार होगा। वार्ड में संचालित तीनों आंगनबाड़ी केंद्र अब तक किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी एवं एमआईसी सदस्य मनीष सिंह उपस्थित रहे। इसी अवसर पर वार्ड की जर्जर नालियों के मरम्मत कार्य का भी शिलान्यास किया गया। यह कार्य 3 लाख 20 हजार रुपये की लागत से कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अमित सिन्हा, पूर्व पार्षद शेखर झरिया, उमा देवी राजवाड़े, श्रीकांत सिन्हा, मिथुन सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, सूरज तिवारी, मुकेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, कबीर गोस्वामी, आशुतोष मिश्रा, सुरेश सोनी, सुरेंद्र सोनी, लाल विजय, समीर सक्षम, साहिल, महेंद्र सूर्यवंशी, वनस झा, आर्यन सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। पार्षद शुभम जायसवाल ने कहा कि वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी विकास कार्य प्राथमिकता के साथ जारी रहेंगे।

छह दिन से हाथी का आतंक,तीन घर तोड़े

-संवाददाता-
सूरजपुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिले के रामानुजनगर-प्रेमनगर वन परिक्षेत्र के बकीरमा इलाके में पिछले छह दिनों से एक हाथी लगातार उत्पात मचा रहा है। जंगल और खेतों में नुकसान पहुंचाने के बाद अब हाथी रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया है,जहां उसने तीन मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार,हाथी लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब उसके आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। ग्रामीण रातभर जागकर निगरानी करने को मजबूर हैं। वन विभाग की टीम हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने,रात में अकेले बाहर नहीं निकलने और हाथी के नजदीक जाने का प्रयास नहीं करने की अपील की है। साथ ही हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

महापौर की पहल पर छह स्थानों पर बनेगा 33/11 केवी उपकेंद्र

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती और बार-बार आने वाले फाल्ट से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छह नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भूमि चयन और आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नगर निगम की पहल पर कलेक्टर ने संबंधित भूमि आवंटित करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पिछले कई महीनों से शहर में विद्युत आपूर्ति बाधित होने और बार-बार फाल्ट आने से आमजन के साथ-साथ पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही थी। बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए महापौर मंजूषा भगत ने नगर निगम के पार्षदों और विद्युत विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई। बैठक में विद्युत विभाग ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ रहे बिजली भार के कारण कटौती और फाल्ट की समस्या बढ़ रही है।

इसका स्थायी समाधान विभिन्न क्षेत्रों में नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित करना है। महापौर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम के साथ पार्षदों के सहयोग से छह स्थानों का चयन कराया।

खाद माफिया से मिलीभगत करने वाले अधिकारी नहीं बचेंगे : कृषि मंत्री

ओवर रेटिंग की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज,राहुल कृषि केंद्र का लाइसेंस निरस्त करने के दिए संकेत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

दरिमा क्षेत्र के नवानगर स्थित राहुल कृषि केंद्र में खाद की ओवर रेटिंग और कालाबाजारी की शिकायत पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि खाद माफिया से मिलीभगत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि शिकायत के बावजूद संबंधित फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने और दुकान संचालक को पहले से सूचना देने के आरोप गंभीर हैं। उन्होंने फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर श्वेता पटेल के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए तथा राहुल कृषि केंद्र का लाइसेंस निरस्त करने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर संबंधित फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर को हटाया गया था, लेकिन बाद में अधिकारियों की कथित मिलीभगत से उसे फिर उसी क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मंत्री ने जिला कृषि अधिकारी (डीडीए) को मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

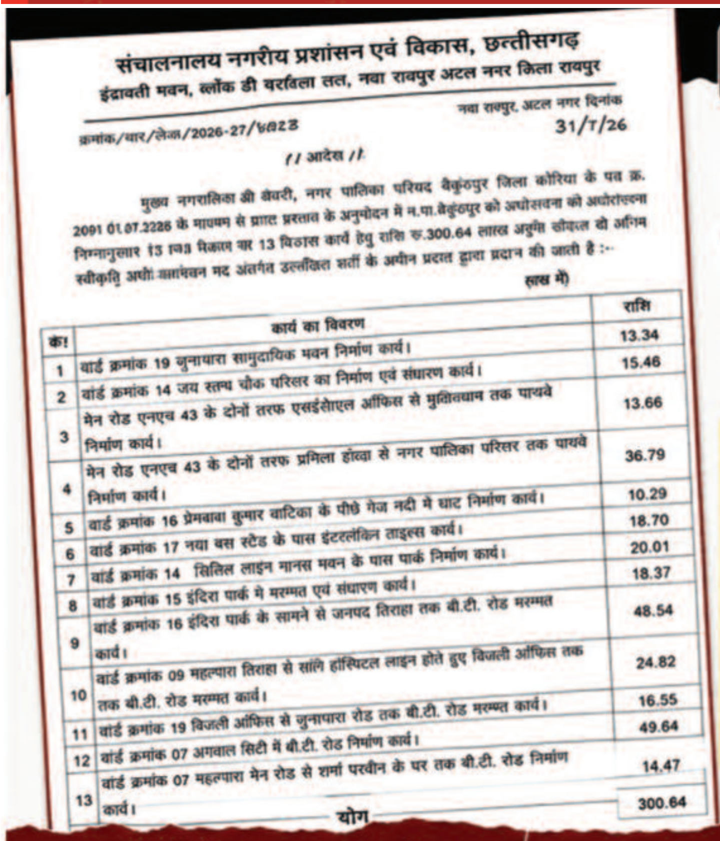

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़
इंद्रावती भवन, ब्लॉक डी थर्डविला तल, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर

क्रमांक/धार/लेखा/2026-27/5023
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31/7/26

// आदेश //

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर जिला कोरिया के पत्र क्र. 2091 01.07.2026 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के अनुमोदन में न.पा.बैकुंठपुर को अधोसंरचना को अधोसंरचना निम्नानुसार 13 नग विकास कार्य 13 विकास कार्य हेतु राशि रु.300.64 लाख अनुमानित लागत की अंतिम स्वीकृति अधो.संरचना मद अंतर्गत उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदत्त द्वारा प्रदान की जाती है :-

(लाख में)

क्र.	कार्य का विवरण	राशि
1	वार्ड क्रमांक 19 जुनापारा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	13.34
2	वार्ड क्रमांक 14 जय स्तम्भ चौक परिसर का निर्माण एवं संधारण कार्य।	15.46
3	मेन रोड एनएच 43 के दोनों तरफ एसईसीएल ऑफिस से मुक्तिधाम तक पाथवे निर्माण कार्य।	13.66
4	मेन रोड एनएच 43 के दोनों तरफ प्रमिला हॉण्डा से नगर पालिका परिसर तक पाथवे निर्माण कार्य।	36.79
5	वार्ड क्रमांक 16 प्रेमबाबा कुमार वाटिका के पीछे गेज नदी में घाट निर्माण कार्य।	10.29
6	वार्ड क्रमांक 17 नया बस स्टैंड के पास इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य।	18.70
7	वार्ड क्रमांक 14 सिविल लाइन मानस भवन के पास पार्क निर्माण कार्य।	20.01
8	वार्ड क्रमांक 15 इंदिरा पार्क में मरम्मत एवं संधारण कार्य।	18.37
9	वार्ड क्रमांक 16 इंदिरा पार्क के सामने से जनपद तिराहा तक बी.टी. रोड मरम्मत कार्य।	48.54
10	वार्ड क्रमांक 09 महलपारा तिराहा से सांगि हॉस्पिटल लाइन होते हुए बिजली ऑफिस तक तक बी.टी. रोड मरम्मत कार्य।	24.82
11	वार्ड क्रमांक 19 बिजली ऑफिस से जुनापारा रोड तक बी.टी. रोड मरम्मत कार्य।	16.55
12	वार्ड क्रमांक 07 अगवाल सिटी में बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	49.64
13	वार्ड क्रमांक 07 महलपारा मेन रोड से शर्मा परवीन के घर तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	14.47
	योग	300.64

चुनाव से पहले बैकुंठपुर नगर पालिका को
3 करोड़ की सौगात!

300.64 लाख की स्वीकृति पर उठे सवाल

जनता के बड़े सवाल

- जय स्तम्भ चौक कहाँ है? जनता पहली बार सुन रही इस नाम को!
- सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित, फिर भी पाथवे निर्माण पर खर्च होंगे 50.45 लाख!
- 20 लाख का पार्क निर्माण – जगह को लेकर विवाद, अन्य की उपेक्षा?
- अग्रवाल सिटी की रोड पर 49.64 लाख – क्या जनता के पैसों का सही उपयोग?
- इंदिरा पार्क के सामने नई सड़क मरम्मत पर उठे सवाल

भेदभाव का आरोप

SamwartKumar Rudra Prasad Roop · 9h

सड़क के ऊपर सड़क नहीं चाहिए,व्यवस्थित सड़क में व्यवस्थित नाली और जल निकासी चाहिए। बजटजाती बदबू से छुटकारा चाहिए। 20 लाख का पार्क नहीं चाहिए हमारे पास एक है वह पर्यापत है,कृण्या उतने लाखों का जल निकास या रोजगार मूलक कार्य दीजिए अथवा अत्यन्त मूलभूत आवश्यकवा पूर्ति में लगा दीजिए, निवेदन ।

प्रशांत प्रताप सिंह · 6h

#बैकुंठपुर की जनता सोचाओ और विचार करे...
आगामी नगर पालिका चुनाव से पहले विकास कार्यों की लंबी सूची जारी की जा रही है। कहीं पार्क निर्माण, कहीं पार्क मरम्मत, कहीं BT रोड, तो कहीं फुटपाथ निर्माण। SECL ऑफिस से मुक्तिधाम तक ₹13.66 लाख और प्रमिला हौंडा से नगर पालिका परिसर तक ₹36.79 लाख, यानी कुल ₹50.45 लाख की लागत से फुटपाथ बनाया जा रहा है। एक ओर जनप्रतिनिधि NH-43 के चौड़ीकरण की बात करते है, तो दूसरी ओर उसी मार्ग पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे है। यदि बाद में इन्हें हटाना पड़े, तो क्या यह जनता के टेक्स के पैसों का सही उपयोग है?

वार्डों में भेदभाव का आरोप, कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों की अनदेखी का दावा

क्या मन मुताबिक बिना प्लान के हो रहे काम या सिर्फ चहेतों को लाभ?

भाजपा जिलाध्यक्ष ने सोशल मीडिया में डाली सूची, कहा – सड़क चौड़ीकरण का काम भी जल्द ही होगा स्वीकृत

जनता, पार्षद, युवाओं ने उठाई आवाज – बड़ी घटना के बाद जागेगा प्रशासन या पहले होगी जांच?

क्या जनता की प्राथमिकताओं पर खर्च होगा पैसा या चुनावी रणनीति के तहत तैयार हुई सूची?

भाजपा जिलाध्यक्ष की पोस्ट से भी सोशल मीडिया पर उठे सवाल,नपा उपाध्यक्ष ने लगाए भेदभाव के आरोप,युवाओं ने कहा...पहले सड़क,नाली और जल निकासी फिर पार्क-पाथवे

3 करोड़ की विकास सूची पर बवाल,20 लाख के पार्क निर्माण ने खड़े किए बड़े सवाल

चुनाव से पहले 3 करोड़ के विकास कार्यों पर विवाद,सोशल मीडिया में जनता ने पूछा...यही है विकास?

बैकुंठपुर में विकास या धन का दुरुपयोग? 3 करोड़ की स्वीकृति पर उठे सवाल

नगर पालिका की 13 विकास योजनाओं पर विवाद,सोशल मीडिया में फूटा जनता का आक्रोश

20 लाख के पार्क से लेकर 50 लाख के पाथवे तक...विकास कार्यों की प्राथमिकता पर सवाल

करोड़ों की स्वीकृति,लेकिन जनता पूछ रही...जरूरत सड़क-नाली की या पार्क की?

विकास कार्यों की स्वीकृति के साथ ही विरोध शुरू,जनता बोली...पहले मूलभूत सुविधाएं,फिर सौंदर्यीकरण

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधोसंरचना मद के अंतर्गत 300.64 लाख रुपये (लगभग 3 करोड़ रुपये) की अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही शहर की राजनीति और विकास कार्यों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है,आमतौर पर किसी नगर निकाय को करोड़ों रुपये की स्वीकृति मिलने पर खुशी और उत्साह का माहौल बनता है, लेकिन बैकुण्ठपुर में इसके ठीक उलट स्थिति देखने को मिल रही है,यहां राशि से अधिक उन कार्यों की सूची चर्चा का विषय बन गई है,जिन पर यह राशि खर्च की जानी है,सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रस्तावित कार्य वास्तव में शहर की वर्तमान जरूरत हैं या फिर चुनावी वर्ष में कुछ विशेष क्षेत्रों और चहेते वार्डों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? यही नहीं,भाजपा के जिला अध्यक्ष तक ने सार्वजनिक रूप से सूची साझा कर कई कार्यों के औचित्य पर सवाल खड़े किए हैं, नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने भी वार्डों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है, जबकि शहर के युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी फेसबुक सहित अन्य माध्यमों से अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

31 जुलाई के आदेश से मिली अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास,छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी आदेश क्रमांक 5023 के माध्यम से नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर को 300.64 लाख रुपये की अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, यह स्वीकृति मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 1 जुलाई 2026 को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर जारी की गई,स्वीकृति आदेश में कुल 13 विकास कार्य शामिल किए गए हैं,इनमें प्रमुख रूप से—वार्ड 19 में जूनापारा सामुदायिक भवन निर्माण,वार्ड 14 में जय स्तंभ चौक परिसर निर्माण एवं संधारण,एनएच-43 पर एसईसीएल कार्यालय से मुक्तिधाम तक पाथवे निर्माण,प्रमिला होंडा से नगर पालिका परिसर तक पाथवे निर्माण,गेज नदी पर घाट निर्माण,नया बस स्टैंड क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स,मानस भवन के पास पार्क निर्माण,इंदिरा पार्क का संधारण,इंदिरा पार्क से जनपद तिराहा तक बीटी रोड मरम्मत,अग्रवाल सिटी में बीटी रोड निर्माण,महलपारा क्षेत्र में सड़क निर्माण सहित अन्य कार्य,दस्तावेज सामने आते ही इन कार्यों को लेकर शहर में बहस शुरू हो गई।

सबसे बड़ा सवाल—जब एनएच-43 चौड़ीकरण होना है तो पाथवे क्यों? सूची में सबसे अधिक चर्चा क्रमांक-3 और क्रमांक-4 को लेकर हो रही है,एक ओर एसईसीएल कार्यालय से मुक्तिधाम तक 13.66 लाख रुपये की लागत से पाथवे निर्माण प्रस्तावित है, दूसरी ओर प्रमिला होंडा से नगर पालिका परिसर तक 36.79 लाख रुपये की लागत से दूसरा पाथवे बनाया जाना है, यानी केवल इन दोनों कार्यों पर लगभग 50.45 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे,यहीं से सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है,शहर में लंबे समय से एनएच-43 चौड़ीकरण की चर्चा चल रही है। जनप्रतिनिधि स्वयं कई मंचों पर सड़क चौड़ीकरण का दावा कर चुके हैं,ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि भविष्य में सड़क चौड़ीकरण होना है,तो उसी मार्ग पर लाखों रुपये खर्च कर पाथवे बनाने का औचित्य क्या है? यदि बाद में चौड़ीकरण के दौरान इन्हें हटाना पड़ा तो क्या यह सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं माना जाएगा?

20 लाख के पार्क पर सबसे ज्यादा आपत्ति–सूची का क्रमांक-7 भी विवादों में है, यहां वार्ड क्रमांक-14 में मानस भवन के पास पार्क निर्माण के लिए 20.01 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं,यहीं से सोशल मीडिया पर सबसे तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई,स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया कि...क्या शहर में पहले से पार्कों की कमी इतनी गंभीर है कि 20 लाख रुपये इसी मद में खर्च किए जाएं? क्या जल निकासी, नालियां,ट्रैफिक,सड़कें और रोजगार जैसी समस्याएं इससे कम महत्वपूर्ण हैं? कुछ लोगों ने तो यहां तक टिप्पणी की कि यदि पार्क ही बनाना है तो 'पूरा चिड़ियाघर ही बना दीजिए',जबकि शहर को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता अधिक है।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी सार्वजनिक रूप से उठाए सवाल–इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग तब मिला जब भाजपा जिला अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकृत कार्यों की सूची सोशल मीडिया पर साझा की, उन्होंने लिखा कि शहर में एक ओर एनएच-43 चौड़ीकरण की बात हो रही है,नगर पालिका बैकुंठपुर के 13 विकास कार्यों के लिए लगभग ?3 करोड़ की स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई है,सड़क, पाथवे एवं अन्य आधारभूत विकास कार्यों से नगर के विकास को नई गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी, इतना ही नहीं,बहुत जल्द बैकुंठपुर के बहुप्रतीक्षित सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी स्वीकृत होने जा रहा है,जिससे जिला मुख्यालय के विकास को एक नया आयाम मिलेगा,उनकी इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई।

नगर पालिका उपाध्यक्ष का आरोप-वार्डों में भेदभाव

नगर पालिका उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के चयन में सभी वार्डों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया, उनका कहना है कि कुछ वार्डों में लगातार बड़े-बड़े कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं जबकि कई वार्डों की मूलभूत आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर दिया गया,उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की अनदेखी का आरोप लगाया, यदि यह आरोप सही हैं तो यह केवल विकास कार्यों का मामला नहीं रहेगा बल्कि राजनीतिक प्राथमिकताओं का भी विषय बन सकता है।

अग्रवाल सिटी की सड़क पर भी सवाल

सूची का क्रमांक-12 भी चर्चा में है,यहां 49.64 लाख रुपये की लागत से अग्रवाल सिटी में बीटी रोड निर्माण प्रस्तावित है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह निजी बिल्डर द्वारा विकसित कॉलोनी है,ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि क्या नगर पालिका द्वारा यहां सार्वजनिक धन से सड़क निर्माण किया जाना उचित है? क्या संबंधित भूमि और सड़क का विधिवत हस्तांतरण नगर पालिका को किया जा चुका है? यदि नहीं,तो यह खर्च किस आधार पर प्रस्तावित किया गया? इन सवालों का उत्तर नगर पालिका प्रशासन से अपेक्षित है।

जय स्तंभ चौक आखिर है कहां?

सूची के क्रमांक-2 में वार्ड क्रमांक-14 में जय स्तंभ चौक परिसर निर्माण एवं संधारण के लिए राशि स्वीकृत की गई है,लेकिन कई नागरिकों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि शहर में यह चौक कहां स्थित है? कुछ लोगों का कहना है कि वे पहली बार इस नाम से किसी स्थान के बारे में सुन रहे हैं, यदि यह स्थान किसी अन्य स्थानीय नाम से जाना जाता है तो नगर पालिका को इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

इंदिरा पार्क से जनपद तिराहा तक सड़क मरम्मत पर भी सवाल...

सूची में 48.54 लाख रुपये की लागत से इंदिरा पार्क के सामने से जनपद तिराहा तक बीटी रोड मरम्मत प्रस्तावित है,स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी मार्ग के एक हिस्से में कुछ माह पूर्व डीएमएफ मद से सड़क निर्माण कराया गया था,ऐसे में अब दोबारा इसी मार्ग पर बड़ी राशि खर्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या वर्तमान सड़क खराब हो चुकी है? यदि नहीं, तो प्राथमिकता किसी अन्य क्षेत्र को मिलनी चाहिए थी।

शहर के युवाओं ने कहा... पहले मूलभूत सुविधाएं

सोशल मीडिया पर शहर के कई युवाओं ने भी अपनी राय रखी,उनका कहना है कि शहर को व्यवस्थित जल निकासी चाहिए,नालियों का निर्माण होना चाहिए, सड़कों की गुणवत्ता सुधरनी चाहिए,रोजगार से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए,उनका कहना है कि केवल पार्क और पाथवे बनाना विकास का पर्याय नहीं हो सकता।

क्या बिना व्यापक जनपरामर्श के तैयार हुई सूची?

पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या इन विकास कार्यों के चयन से पहले शहर के नागरिकों, पार्षदों और संबंधित समितियों से व्यापक राय ली गई? यदि जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों को विश्वास में लेकर प्राथमिकताएं तय की जातीं तो संभवतः इतनी आपत्तियां सामने नहीं आतीं, यही कारण है कि अब यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं विकास कार्यों की सूची केवल प्रशासनिक स्तर पर या सीमित दायरे में तो तैयार नहीं कर ली गई?

जनता पूछ रही...क्या चुनावी वर्ष का असर?

नगर पालिका चुनाव निकट हैं,ऐसे समय में करोड़ों रुपये की स्वीकृति और कार्यों की सूची सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, कुछ लोग इसे चुनाव पूर्व विकास कार्यों की शुरुआत मान रहे हैं,जबकि आलोचकों का कहना है कि जनता की वास्तविक प्राथमिकताओं की जगह दृश्यात्मक कार्यों को अधिक महत्व दिया गया है,हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी उपलब्ध नहीं है।

नगर पालिका का पक्ष भी महत्वपूर्ण

विवादों के बीच यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आए,संभव है कि प्रत्येक कार्य के पीछे तकनीकी आवश्यकता,भविष्य की योजना या प्रशासनिक औचित्य हो,इसी प्रकार सड़क चौड़ीकरण,भूमि हस्तांतरण, पार्क निर्माण,पाथवे और अन्य कार्यों को लेकर भी नगर पालिका अपनी स्पष्ट स्थिति रख सकती है,संतुलित और निष्पक्ष पत्रकारिता की दृष्टि से इन सभी बिंदुओं पर नगर पालिका प्रशासन का पक्ष प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा।

अब निगाहें प्रशासन पर...

करीब 3 करोड़ रुपये की स्वीकृति बैकुण्ठपुर के विकास के लिए निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन इस राशि का उपयोग किन प्राथमिकताओं पर और किस पारदर्शिता के साथ होगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है,सोशल मीडिया पर उठ रही आपत्तियां,जनप्रतिनिधियों के बयान, युवाओं की प्रतिक्रियाएं और नगर पालिका उपाध्यक्ष के आरोप यह संकेत दे रहे हैं कि शहर अब विकास कार्यों की केवल घोषणा नहीं,बल्कि उनकी उपयोगिता और दीर्घकालिक प्रभाव पर भी सवाल पूछ रहा है,अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन इन आपत्तियों का क्या जवाब देता है,क्या विवादित कार्यों की समीक्षा की जाती है,और क्या वास्तव में यह राशि शहर की वास्तविक जरूरतों पर खर्च होगी या चुनावी मौसम की राजनीति में यह मुद्दा और अधिक गर्माएगा।

कोरिया पुलिस में 'आपसी सहमति' का नया सिस्टम? बिना आदेश आरक्षक की अदला-बदली पर उठे सवाल

लाइन में पदस्थ आरक्षक थाने में...और थाने का आरक्षक लाइन में...क्या सब कुछ मौखिक व्यवस्था से चल रहा है... या विभागीय रिकॉर्ड में भी दर्ज है?

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिला पुलिस में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन में पदस्थ एक आरक्षक को बिना किसी सार्वजनिक स्थानांतरण आदेश के पटना थाना में कार्य करने भेज दिया गया है,जबकि पटना थाना में पदस्थ एक आरक्षक को पुलिस लाइन बुला लिया गया है,बताया जा रहा है कि यह पूरी व्यवस्था कथित तौर पर 'आपसी सहमति'से संचालित हो रही है,यदि यह जानकारी सही है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस विभाग में पदस्थापना और कार्यस्थल का निर्धारण अब लिखित आदेशों के बजाय मौखिक सहमति से होने लगा है?

पुलिस विभाग में हर आदेश का होता है रिकॉर्ड–पुलिस विभाग अनुशासन और लिखित आदेशों पर आधारित व्यवस्था माना जाता है,किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की पदस्थापना,कार्यमुक्ति, नवीन पदस्थापना अथवा अस्थायी संबद्धता तक का स्पष्ट आदेश जारी किया जाता है,जिसका रिकॉर्ड विभागीय अभिलेखों में सुरक्षित रहता है,ऐसे में यदि कोई आरक्षक अपने मूल पदस्थापना स्थल से हटकर दूसरे स्थान पर कार्य कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसका विभागीय आदेश कहां है।

क्या कोई लिखित आदेश जारी हुआ?–सूत्रों का दावा है कि लाइन में पदस्थ आरक्षक वर्तमान में पटना थाना में कार्य कर रहा है और पटना थाना का आरक्षक लाइन में है,यदि ऐसा है तो प्रश्न उठता है–क्या इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कोई लिखित आदेश जारी किया गया? यदि आदेश जारी हुआ तो उसकी प्रति कहां उपलब्ध है? यदि आदेश जारी नहीं हुआ तो किस अधिकार के तहत कार्यस्थल बदला गया? क्या संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका भी उसी आधार पर संचालित हो रही है?

'आपसी सहमति' क्या विभागीय प्रक्रिया का विकल्प हो सकती है?–पुलिस विभाग में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का कार्यस्थल स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है, यदि'आपसी सहमति' के आधार पर कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार थाने और लाइन के बीच कार्य करने लगें तो इससे विभागीय अनुशासन, जवाबदेही और प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है,यदि यह केवल अस्थायी व्यवस्था है, तब भी उसके लिए सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश होना आवश्यक माना जाता है।

जवाबदेही किसकी?–यदि वास्तव में बिना आदेश के यह व्यवस्था संचालित हो रही है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इसकी अनुमति किस अधिकारी ने दी? संबंधित थाना प्रभारी की क्या भूमिका है? क्या पुलिस लाइन के प्रभारी अधिकारी को इसकी जानकारी है? क्या पुलिस अधीक्षक कार्यालय इस व्यवस्था से अवगत है?

विभागीय पारदर्शिता पर उठे सवाल–पुलिस जैसी अनुशासित सेवा में पारदर्शिता और अभिलेखीय व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता मानी जाती है,इसलिए यदि कोई कर्मचारी उस स्थान पर कार्य कर रहा है जहां उसकी विधिवत पदस्थापना नहीं है,तो यह प्रशासनिक प्रक्रिया की दृष्टि से जांच का विषय बन सकता है।

विभाग से अपेक्षित है स्पष्ट स्थिति–इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, यदि सूत्रों से प्राप्त जानकारी सही है तो विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित आरक्षकों की वास्तविक पदस्थापना कहां है? क्या उनके कार्यस्थल परिवर्तन का कोई लिखित आदेश जारी किया गया है? यदि नहीं,तो यह व्यवस्था किस आधार पर संचालित की जा रही है? फिलहाल यह मामला सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है,यदि विभाग इस संबंध में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या दस्तावेज जारी करता है, तो वही अंतिम और प्रमाणिक स्थिति मानी जाएगी।

कबाड़ में खड़ी परमिटधारी बस के नाम पर चल रहा दूसरा वाहन,परिवहन विभाग की निगरानी पर गंभीर सवाल

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया जिले में निजी बस संचालन को लेकर उठा बड़ा सवाल,यात्रियों की सुरक्षा से कथित खिलवाड़ की आशंका

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां/मनेंद्रगढ़,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) एवं कोरिया जिले में निजी बसों के संचालन को लेकर ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं,जिनका जवाब परिवहन विभाग के पास होना चाहिए, स्थानीय लोगों और यात्रियों का आरोप है कि कुछ बस संचालक जिस मार्ग (रूट) के लिए परमिट प्राप्त किए हुए हैं,उसी मार्ग पर बस नहीं चला रहे, बल्कि दूसरे मार्गों पर अन्य वाहनों का संचालन कर रहे हैं,इससे भी गंभीर आरोप यह है कि जिस बस के नाम और नंबर पर परमिट जारी है,वह कथित रूप से वर्षों से गैरेज या कबाड़ में खड़ी है,जबकि उसी परमिट अथवा नंबर का उपयोग किसी अन्य बस के संचालन में किया जा रहा है,यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह केवल मोटरयान नियमों का उल्लंघन भर नहीं,बल्कि यात्रियों की सुरक्षा,बीमा दावों और प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

परमिट एक मार्ग का संचालन दूसरे मार्ग पर!

क्षेत्र में चर्चा है कि कुछ बसों को जिन मार्गों के लिए विधिवत परमिट मिला है,वे उन मार्गों पर नियमित संचालन नहीं कर रही हैं,आरोप है कि उनकी जगह दूसरे मार्गों पर बसें चलाई जा रही हैं,बताया जा रहा है कि मनेंद्रगढ़-उधनापुर-जरौधा,बैकुंठपुर-पोड़ी-बचरा तथा चिरमिरी-प्रेमनगर-खड़गवां-मनेंद्रगढ़ सहित कई मार्गों पर बस संचालन को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं,स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी रूट के लिए जारी परमिट का उपयोग दूसरे रूट पर किया जा रहा है तो इससे पूरी परिवहन व्यवस्था की पारदर्शिता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

कबाड़ में खड़ी बस,सड़क पर दौड़ रहा दूसरा वाहन?

सबसे गंभीर आरोप यह है कि जिस वाहन के नाम पर परमिट जारी है, वह कथित रूप से संचालन में ही नहीं है,चर्चा है कि वह वाहन लंबे समय से गैरेज अथवा कबाड़ में खड़ा है,जबकि उसी परमिट अथवा नंबर के सहारे दूसरा वाहन यात्रियों को लेकर सड़क पर दौड़ रहा है,यदि ऐसा हो रहा है तो कई गंभीर कानूनी प्रश्न खड़े होते हैं सड़क पर चल रही बस की वास्तविक पहचान क्या है? फिटनेस प्रमाणपत्र किस वाहन का है? बीमा किस वाहन के नाम पर प्रभावी है? दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी किसकी तय होगी? इन सवालों के जवाब केवल जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकते हैं।

यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला...

प्रतिदिन सैकड़ों यात्री इन बसों से सफर करते हैं,अधिकांश यात्रियों को यह जानकारी ही नहीं होती कि जिस बस में वे बैठे हैं,वह वास्तव में उसी वाहन का संचालन है जिसके नाम पर परमिट जारी हुआ है या नहीं,यदि किसी अन्य वाहन का संचालन किया जा रहा है और दस्तावेज किसी दूसरे वाहन के हैं,तो दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावे,कानूनी दायित्व और यात्रियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

परिवहन विभाग की निगरानी पर उठ रहे सवाल-पूरा मामला परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है, यदि विभाग नियमित रूप से बसों की जांच करता है तो–परमिट किस वाहन के नाम पर है? सड़क पर वास्तव में कौन-सा वाहन चल रहा है? वाहन स्वीकृत मार्ग पर संचालित हो रहा है या नहीं? जैसे बुनियादी तथ्यों की पुष्टि अब तक क्यों नहीं हुई? स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नियमित निरीक्षण प्रभावी ढंग से हो रहे होते तो ऐसी शिकायतें वर्षों तक चर्चा का विषय नहीं बनतीं।

क्या केवल कागजों में हो रही निगरानी?

क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि विभागीय निरीक्षण अधिकतर दस्तावेजी औपचारिकताओं तक सीमित रह जाते हैं,जबकि वास्तविक संचालन की भौतिक जांच बहुत कम होती है,हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

दुर्घटना हुई तो जिम्मेदार कौन होगा?-यदि किसी कथित अनियमित बस का दुर्घटना में उपयोग होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बस संचालक? वाहन मालिक? चालक? या वह अधिकारी जिसने कथित अनियमितता के बावजूद समय रहते जांच नहीं की? विशेषज्ञों का मानना है कि दुर्घटना के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि उससे पहले नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम केवल औपचारिकता नहीं, यात्रियों की सुरक्षा का आधार- परिवहन व्यवस्था में परमिट,फिटनेस, बीमा और वाहन की वास्तविक पहचान केवल कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा का आधार होती है,यदि किसी वाहन का परमिट,फिटनेस और बीमा एक बस के नाम पर हो तथा सड़क पर दूसरी बस चल रही हो,तो यह स्थिति गंभीर जांच का विषय बन सकती है।

स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें...

क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग से मांग की है कि जिले में संचालित सभी निजी बसों की विशेष जांच कराई जाए, जांच में विशेष रूप से यह देखा जाए—परमिट किस वाहन के नाम और नंबर पर जारी है,सड़क पर वास्तव में कौन-सा वाहन संचालित हो रहा है,बस स्वीकृत मार्ग पर चल रही है या नहीं, फिटनेस प्रमाणपत्र वैध है या नहीं, बीमा की स्थिति क्या है,नंबर प्लेट और दस्तावेजों में कोई विसंगति तो नहीं,परमिटधारी बस के स्थान पर किसी अन्य वाहन का संचालन तो नहीं किया जा रहा।

जांच से ही सामने आएगा सच...

वर्तमान में लगाए जा रहे आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए आवश्यक है कि परिवहन विभाग एवं सक्षम प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की भौतिक एवं दस्तावेजी जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करें,यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित बस संचालकों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए,क्योंकि यह मामला केवल परमिट या दस्तावेजों का नहीं, बल्कि उन सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा का है जो प्रतिदिन इन बसों में सफर करते हैं।

अतिक्रमण बना तबाही की वजह! गाड़ा सिली नाला का चेक डैम टूटा,लाखों की जल संरचना ध्वस्त

प्राकृतिक जल प्रवाह में बाधा बनने से बढ़ा दबाव,ग्रामीणों ने अवैध अतिक्रमण हटाने और दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग...

-ओंकार पाण्डेय-

रामानुजनगर/सूरजपुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। ग्राम पंचायत परशुरामपुर के अंतर्गत गाड़ा सिली नाला पर जल संरक्षण और सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित चेक डैम भारी बारिश और तेज जलप्रवाह के दौरान क्षतिग्रस्त होकर टूट गया,इस घटना से न केवल लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि क्षेत्र के किसानों की सिंचाई व्यवस्था पर भी संकट मंडराने लगा है,घटना के बाद ग्रामीणों ने इस नुकसान के लिए नाले के प्राकृतिक जल प्रवाह क्षेत्र में किए गए कथित अवैध अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

भारी बारिश में नहीं झेल पाया पानी का दबाव-क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण गाड़ा सिली नाला उफान पर था, तेज जलप्रवाह के बीच चेक डैम पर अत्यधिक दबाव बना,जिसके चलते संरचना का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और देखते ही देखते पूरा चेक डैम टूट गया, इससे बड़ी मात्रा में पानी बह गया और जल संरक्षण की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो गई।

ग्रामीणों का आरोप—अतिक्रमण ने बदला पानी का रास्ता-ग्रामीणों का कहना है कि नाले के प्राकृतिक जल प्रवाह क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से खेती और अतिक्रमण किया जा रहा था,इससे पानी के बहाव का प्राकृतिक मार्ग संकरा और बाधित हो गया,उनका आरोप है कि बारिश के दौरान पानी का पूरा दबाव चेक डैम पर आ गया,जिसके कारण वह इस दबाव को सहन नहीं कर सका और क्षतिग्रस्त हो गया,ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते जल प्रवाह क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया होता तो संभवतः यह स्थिति नहीं बनती।

लाखों की सरकारी संपत्ति हुई बर्बाद-चेक डैम के टूटने से शासन द्वारा जल संरक्षण और सिंचाई के लिए कराए गए लाखों रुपये के निर्माण कार्य को बड़ा नुकसान पहुंचा है,इस संरचना के माध्यम से आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता था,अब इसके टूट जाने से आगामी समय में खेती पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

सिंचाई व्यवस्था पर पड़ेगा असर-स्थानीय किसानों का कहना है कि चेक डैम में पानी रुकने से भूजल स्तर भी बेहतर रहता था और खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता था। अब संरचना के ध्वस्त होने से जल संग्रहण की व्यवस्था प्रभावित होगी,जिससे रबी और अन्य फसलों की सिंचाई पर असर पड़ सकता है।

प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग-ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए,यदि चेक डैम के टूटने के पीछे अवैध अतिक्रमण या किसी प्रकार की लापरवाही जिम्मेदार पाई जाती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अतिक्रमण हटाने और पुनर्निर्माण की मांग-ग्रामीणों ने प्रशासन से गाड़ा सिली नाला के प्राकृतिक जल प्रवाह क्षेत्र से सभी अवैध अतिक्रमण हटाने, टूटे हुए चेक डैम का शीघ्र पुनर्निर्माण कराने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है।

प्रशासन का पक्ष आना बाकी-समाचार लिखे जाने तक इस पूरे मामले में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों या विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था,ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन मौके का निरीक्षण कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगा ताकि जल संरक्षण की व्यवस्था दोबारा बहाल हो सके और किसानों को राहत मिल सके।

चार महीने बाद भी जांच अधर में! सरकारी डॉक्टर पर निजी प्रैक्टिस के आरोपों पर प्रशासन की चुप्पी,शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को फिर सौंपा स्मरण पत्र

सरकारी सेवा में रहते हुए निजी क्लीनिक,एक्स-रे और सोनोग्राफी संचालन के आरोप,डॉक्टर ने कहा...सभी आरोप निराधार, क्लीनिक विधिवत पंजीकृत

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। जिले के रामानुजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक सरकारी चिकित्सक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर चार माह बाद भी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आने से मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है,शिकायतकर्ता प्रमोद पांडे ने जिला कलेक्टर को स्मरण पत्र (रिमाइंडर) सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराए जाने की मांग की है,शिकायतकर्ता का कहना है कि मार्च 2026 में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद न तो उन्हें जांच की स्थिति से अवगत कराया गया और न ही किसी कार्रवाई की जानकारी दी गई,यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक सरकारी चिकित्सक पर शासकीय सेवा के दौरान निजी क्लीनिक संचालन, एक्स-रे एवं सोनोग्राफी जैसी सेवाओं के संचालन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि संबंधित चिकित्सक ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए अपना पक्ष स्पष्ट किया है।

27 मार्च को की गई थी शिकायत, चार माह बाद फिर पहुंचा मामला कलेक्टर तक-शिकायतकर्ता प्रमोद पांडे के अनुसार उन्होंने 27 मार्च 2026 को जिला कलेक्टर सूरजपुर को विस्तृत लिखित शिकायत सौंपकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर में पदस्थ एमबीबीएस चिकित्सक डॉ. डी.के.विश्वकर्मा के विरुद्ध जांच की मांग की थी,शिकायत में आरोप

लगाया गया था कि संबंधित चिकित्सक शासकीय सेवा में रहते हुए निजी क्लीनिक का संचालन कर रहे हैं, साथ ही बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति के एक्स-रे एवं सोनोग्राफी (अल्ट्रासाउंड) सेवाएं भी संचालित किए जाने का आरोप लगाया गया था, अब चार माह बीत जाने के बाद शिकायतकर्ता ने पुनः स्मरण पत्र देकर प्रशासन से मामले में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।

कार्रवाई नहीं होने से बढ़ रहा संदेह-शिकायतकर्ता का कहना है कि शिकायत के बाद यदि समय पर जांच प्रारंभ हो जाती तो अब तक पूरा मामला स्पष्ट हो चुका होता, उनका आरोप है कि कार्रवाई में हो रही देरी से आम लोगों के बीच यह संदेश जा रहा है कि प्रभावशाली लोगों के मामलों में जांच आगे नहीं बढ़ती, उन्होंने कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होना प्रशासन की जिम्मेदारी है,जांच में यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो संबंधित अधिकारी को क्लीन चिट मिलनी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

स्मरण पत्र में उठाई गई प्रमुख मांगें-कलेक्टर को सौंपे गए स्मरण पत्र में शिकायतकर्ता ने मांग की है कि 27 मार्च 2026 को प्रस्तुत शिकायत की तत्काल उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए,जांच पूरी होने तक निजी क्लीनिक,एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेवाओं के संचालन की वैधानिक स्थिति की जांच की जाए, संबंधित अभिलेखों एवं अनुमति पत्रों का परीक्षण किया जाए,यदि जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित प्रावधानों के तहत विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए।

शिकायतकर्ता का दावा—वर्षों से चल रहा है निजी संचालन- प्रमोद पांडे का दावा है कि संबंधित चिकित्सक पिछले लगभग दस वर्षों से निजी क्लीनिक तथा जांच सेवाओं का संचालन कर रहे हैं,उनका कहना है कि यदि प्रशासन चाहे तो संबंधित दस्तावेजों एवं अभिलेखों की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने ला सकता है, हालांकि इस दावे की अभी तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसकी पुष्टि केवल विभागीय अथवा प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी।

डॉ. डी.के. विश्वकर्मा ने सभी आरोपों को किया खारिज-पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर में पदस्थ एमबीबीएस चिकित्सक डॉ. डी.के. विश्वकर्मा ने कहा कि उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप तथ्यहीन एवं निराधार हैं,उन्होंने कहा मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, मुझे आपके माध्यम से ही इन आरोपों की जानकारी मिली है,जहां तक एक्स-रे सेवा का प्रश्न है, रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण पिछले लगभग चार माह से एक्स-रे मशीन बंद है। वहीं सोनोग्राफी मशीन भी पिछले लगभग एक वर्ष से बंद है और उससे कोई जांच नहीं की जा रही है,जिस क्लीनिक के संचालन की बात कही जा रही है,वह नर्सिंग होम अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है,विभागीय जांच के संबंध में मुझे अब तक कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है,यदि विभाग द्वारा जांच की जा रही है, तो मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा।

अब प्रशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण-इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता और संबंधित चिकित्सक के दावे एक-दूसरे से भिन्न हैं, ऐसे में वास्तविक स्थिति केवल सक्षम प्रशासनिक एवं विभागीय जांच से ही स्पष्ट हो सकती है,यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच होती है तो यह भी स्पष्ट होगा कि क्या संबंधित चिकित्सक द्वारा निजी क्लीनिक का संचालन सेवा नियमों के अनुरूप था? एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेवाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी? संबंधित क्लीनिक एवं चिकित्सा सेवाओं के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमतियां उपलब्ध थीं या नहीं? शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई की गई?

पारदर्शी जांच से ही दूर होगा संशय

यह मामला केवल एक चिकित्सक या एक शिकायत तक सीमित नहीं है,बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और शिकायतों के समयबद्ध निराकरण से भी जुड़ा हुआ है, यदि जांच निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरी की जाती है तो इससे न केवल शिकायतकर्ता और संबंधित चिकित्सक के बीच उठे विवाद का समाधान होगा,बल्कि आम नागरिकों का प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत होगा,फिलहाल पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष विभागीय जांच के बाद ही सामने आएगा,जांच पूरी होने तक लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं मानी जा सकती और संबंधित चिकित्सक ने आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया है।

ओटीटी पर आ रही हैं 8 नई फिल्में और सीरीज

इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में मचाई धूम, अब भारत में लाएगी डर का नया पैगाम

9 अक्टूबर को थिएटर्स में होगा खौफनाक मंजर

अक्टूबर में सिनेमाघरों में दर्शकों को उस फिल्म का भी दीदार होगा,जो कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में धूम मचा चुकी है। यह मूवी इतनी डरावनी है कि हाथ-पांव कांपने लगेंगे। साल 2026 का सेकंड हाफ बॉलीवुड फैंस के लिए काफी रोमांचक होने वाला है,क्योंकि अगस्त से लेकर नवंबर तक आवारापन 2,बंटवारा 1947,टॉक्सिक,दृश्यम 3 और रामायण जैसी कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करने वाली हैं।2026 की नई रिलीज फिल्मों में एक और बड़ी फिल्म का नाम शामिल हो चुका है,जो इंटरनेशनल मंच पर पहले से ही सफलता के झंडे गाड़ चुकी है और अब सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। कौन-सी है वह फिल्म जो 9 अक्टूबर को लिखेगी डर का एक नया पैगाम?

9 अक्टूबर को थिएटर्स में धमाल मचाएगी यह हॉरर फिल्म

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं,वह मल्टी-लैंग्वेज फॉक हॉरर फिल्म बोक्शी है,जिसका निर्देशन भार्गव सैकिया ने किया है। प्रोडक्शन हाउस द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक,साल 2025 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम में फिल्म का प्रीमियर किया गया था। स्टेटमेंट में मेकर्स ने यह भी बताया कि यह अकेली ऐसी इंडियन फीचर फिल्म है,जिसे साल 2025 में अलग-अलग फेस्टिवल्स में शामिल किया गया। मूवी को स्पेन में सिटजेस इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल,स्विट्जरलैंड में न्यूचैटेल इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल और ऑस्ट्रेलिया में एसएक्सएसडब्ल्यू सिडनी में दिखाया गया। इंटरनेशनल मंच पर धमाल मचा चुकी फिल्म बोक्शी अब 9 अक्टूबर को हिंदी,इंग्लिश और नेपाली भाषा में भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। फिल्म की रिलीज पर मूवी के निर्देशक-निर्माता भार्गव ने बातचीत करते हुए कहा,2025 के एक्साइटिंग फेस्टिवल टूर के बाद हम खुश हैं कि इस मूवी को हम भारतीय ऑडियंस के लिए लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म खास तौर पर यंग ऑडियंस के लिए है। बोक्शी ऐसी हॉरर फिल्म है, जिसे बड़े पर्दे पर जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए।

क्या है बोक्शी की कहानी?

फिल्म की कहानी की बात करें तो यह फिल्म एक 17 साल की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी मां के गायब होने के कारण दर्द और मानसिक तनाव से जूझ रही है। उन्हीं दिनों उसकी इतिहास की टीचर बच्चों को सिक्किम के जंगलों में प्राचीन चीजों के बारे में बताने के लिए सभी को लेकर एक यात्रा पर निकलती है। जंगल में जिस स्थान पर वे जाते हैं, उसका संबंध बोक्शी की पूजा करने वाले एक समुदाय से जुड़ा हुआ है। कौन है बोक्शी और क्यों सिक्किम के घने जंगलों के बीच की जाती थी उसकी पूजा, यह आपको 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में पता लगेगा। बोक्शी लोककथाओं पर आधारित फिल्म है, जिसमें प्रसन्ना बिष्ट, मानसी मुल्तानी और सिद्धार्थ शॉ ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा शेरनाज पटेल भी अहम भूमिका में हैं।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस सप्ताह दर्शकों के लिए मनोरंजन का जबरदस्त खजाना खुलने जा रहा है। शुक्रवार, 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स और जी5 पर एक साथ आठ नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। इनमें युद्ध पर आधारित डॉक्यूड्रामा, रोमांटिक ड्रामा, साइंस फिक्शन, हॉरर, एक्शन कॉमेडी और फैमिली ड्रामा जैसी अलग-अलग शैलियों की कहानियां शामिल हैं। ऐसे में अगर आप वीकेंड पर घर बैठे कुछ नया और रोमांचक देखना चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए खास साबित हो सकता है।

सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर आने वाली डॉक्यूड्रामा सीरीज **ऑपरेशन सफेद सागर : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कारगिल वॉर** की। यह सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा निभाई गई अहम भूमिका को पर्दे पर पेश करेगी। निर्देशक ओनी सेन ने इस सीरीज के जरिए उन अनकहे पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है, जो कारगिल युद्ध के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। देशभक्ति और सैन्य अभियानों में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए यह एक खास पेशकश होगी।

रोमांटिक कहानियां पसंद करने वालों के लिए नेटफ्लिक्स पर **अवर स्टिकी लव** रिलीज हो रही है। यह एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, जिसकी कहानी एक महिला वकील के इर्द-गिर्द घूमती है। दुर्घटना के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है और वह एक बॉक्सिंग कोच के साथ रहने लगती है। बॉक्सिंग कोच खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताता है। इसके बाद दोनों के रिश्ते में आने वाले उतार-चढ़ाव और भावनात्मक मोड़ इस सीरीज का मुख्य आकर्षण हैं।

तमिल सिनेमा के प्रशंसकों के लिए नेटफ्लिक्स पर **इधयम मुरली** भी रिलीज होगी। यह एक रोमांटिक फिल्म है, जिसमें एक ऐसे युवक की कहानी दिखाई गई है जो एकतरफा प्यार की भावनाओं से जूझ रहा है। जिंदगी में कई बदलाव आने के बावजूद उसके दिल में बसे एहसास खत्म नहीं होते और यही उसकी कहानी का आधार बनते हैं। साइंस फिक्शन फिल्मों के शौकीनों के लिए नेटफ्लिक्स **मिक्की 17** लेकर आ रहा है। वर्ष 2025 में बनी यह हॉलीवुड फिल्म भविष्य की दुनिया पर आधारित है, जहां इंसान अंतरिक्ष में नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिशन के तहत **मिक्की 17** नाम के एक कर्मचारी को बर्फ से ढके एक ग्रह की खोज के लिए भेजा जाता है। रोमांच, विज्ञान और रहस्य से भरपूर यह फिल्म दर्शकों को अलग अनुभव देने का दावा करती है।

नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होने वाली **लव हर्ट्स** एक अमेरिकी एक्शन-कॉमेडी फिल्म है। इसकी कहानी एक ऐसे पूर्व अपराधी की है जिसने अपराध की दुनिया छोड़कर रियल एस्टेट एजेंट का जीवन अपना लिया है। हालांकि परिस्थितियां उसे एक बार फिर पुराने खतरनाक रास्ते पर लौटने के लिए मजबूर कर देती हैं। फिल्म में एक्शन और हास्य का संतुलित मिश्रण देखने को मिलेगा। हॉरर और साइंस फिक्शन पसंद करने वालों के लिए **द लास्ट हाउस** भी इसी दिन स्ट्रीम होगी। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपने ही घर में रहस्यमयी तरीके से कैद हो जाता है। वे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते और उन्हें एक खतरनाक ऊर्जा से अपनी जान बचानी पड़ती है। रहस्य और डर से भरपूर यह फिल्म दर्शकों को अंत तक बांधे रखने का प्रयास करती है। वहीं, जी5 अपने दर्शकों के लिए दो तमिल फिल्में लेकर आ रहा है। पहली फिल्म **लेनिन** है, जो एक एक्शन-रोमांटिक ड्रामा है। इसकी कहानी श्रीरामपुरम गांव के एक युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो गांव के एक पारंपरिक त्योहार के दौरान होने वाली हिंसा को रोकने की कोशिश करता है। फिल्म में सामाजिक संदेश के साथ एक्शन और भावनात्मक पहलुओं को भी दिखाया गया है। दूसरी फिल्म **नूरू सामी** एक फैमिली ड्रामा है,जो मां और बेटे के गहरे रिश्ते पर आधारित है। भावनात्मक कहानी वाली इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.7 बताई जा रही है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। कुल मिलाकर 7 अगस्त का दिन ओटीटी प्रेमियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। युद्ध,रोमांस,हॉरर,साइंस फिक्शन,एक्शन,कॉमेडी और फैमिली ड्रामा जैसी विविध शैलियों की आठ नई फिल्में और सीरीज एक साथ रिलीज हो रही हैं।

फिल्म मकुटम के ट्रेलर की रिलीज डेट का हुआ एलान,नया पोस्टर भी जारी

मकुटम ने ट्रेलर लॉन्च की तारीख का ऐलान करके फिल्म के प्रमोशन कैंपेन की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा ट्रेलर 7 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा। मेकर्स को भरोसा है कि ट्रेलर इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ाएगा और फिल्म की थिएटर रिलीज़ के लिए माहौल तैयार करेगा।

टीजर, फर्स्ट-लुक पोस्टर और गानों से उत्सुकता जगाने के बाद, उम्मीद है कि ट्रेलर दर्शकों को मकुटम की एक्शन से भरपूर दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी झलक दिखाएगा।विशाल के करियर में मकुटम का खास महत्व है क्योंकि यह उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। फिल्म में अंजलि और दुशारा विजयन मुख्य महिला भूमिकाओं में हैं और यह 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। इसका संगीत जी.वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है, जबकि एक्शन सीन दिलीप सुब्बारायन ने कोरियोग्राफ किए हैं, जिससे एक ज़बरदस्त थिएटर अनुभव मिलने का संकेत मिलता है।

रश्मिका मंदाना का सिंपल रूटीन : सोना,खाना और ऑरा के साथ मस्ती

हाल ही में हिप बोन (कूल्हे की हड्डी) में चोट लगने के बाद, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया पर अपने इंस्टा परिवार के साथ ठीक होने के दौरान की अपनी दिनचर्या शेयर की। एनिमल एक्ट्रेस ने बताया कि घर पर ठीक होने का इंतज़ार करते हुए उनके दिन में बहुत सोना,खाना,पज़ल सुलझाना,पढ़ना और अपने प्यारे डॉग ऑरा के साथ खेलना शामिल है। इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट डियर डायरी पोस्ट में रश्मिका ने लिखा, डियर डायरी। हम्म...कहाँ से शुरू करूँ? मेरे दिन अच्छे गुज़र रहे हैं...खूब सोना और ठीक होना, पज़ल और थोड़ी पढ़ाई-लिखाई, कुछ शो देखना, बालों और स्किन की बहुत ज़रूरी देखभाल करना...और मीटिंग्स व परिवार के साथ समय बिताना!! द गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस ने आगे लिखा,शादी की तस्वीरें और वीडियो देख रही हूँ क्योंकि मुझे अब तक सही समय नहीं मिला था...मेरा रूटीन कुछ ऐसा है-उठना, और अलार्म की ज़रूरत नहीं (यै!),बस जब शरीर कहे तब उठना...दिन में 2 बार खाना ताकि ज़्यादा खाने से बच सकूँ मीटिंग्स ऑरा के साथ पज़ल या पढ़ना (जब वह तैयार हो)...कोई शो देखना और फिर सो जाना...कभी-कभी जिंदगी की रफ़्तार धीमी करना बुरा नहीं है, है ना!

खेल समाचार

महिला एशिया कप 28 अगस्त से

एसीसी ने शेड्यूल घोषित किया, भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रूप में

महिला एशिया कप 2026 की शुरुआत 28 अगस्त से यूएई में होगी। भारत और पाकिस्तान की टीम को एक ही ग्रूप में रखा गया है और 5 सितंबर को दोनों का मुकाबला होगा।

नई दिल्ली,06 अगस्त 2026। महिला एशिया कप 2026 की शुरुआत 28 अगस्त से हो रही है। यूएई की मेजबानी में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट का शेड्यूल घोषित कर दिया है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच 5 सितंबर को मुकाबला होगा। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। महिला एशिया कप 2026 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत टूर्नामेंट का टीम है और 7 बार खिताब अपने नाम कर चुका है।

8 टीमों को 2 ग्रूप में बांटा गया

महिला एशिया कप 2026 में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हें 4-4 के दो ग्रूप में बांटा गया है। ग्रूप ए में भारत और पाकिस्तान के अलावा हांगकांग और थाईलैंड को जगह मिली है। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका,बांग्लादेश,यूएई और इंडोनेशिया है। थाईलैंड और हांगकांग के बीच टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा। भारतीय टीम थाईलैंड के खिलाफ 30 अगस्त को अपना पहला मुकाबला खेलेगी। सभी मैचों की शुरुआत भारतीय समय अनुसार सभी मुकाबलों की शुरुआत रात 8 बजे होगी।

13 सितंबर को होगा महिला एशिया कप का फाइनल

महिला एशिया कप 2026 के दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमों को सेमीफाइनल में एंट्री मिलेगी। 10 सितंबर को पहला जबकि 11 को दूसरा सेमीफाइनल होगा। 13 सितंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही होंगे। श्रीलंका इस टूर्नामेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है। 2024 में भारत को फाइनल में 8 विकेट से हराकर टीम ने पहली बार खिताब जीता था।

महिला एशिया कप 2026 का शेड्यूल घोषित

तारीख	मुकावला	समय (भारतीय समयानुसार)
28 अगस्त	थाईलैंड vs हांगकांग	रात 8:00 बजे
29 अगस्त	श्रीलंका vs यूएई	रात 8:00 बजे
30 अगस्त	भारत vs थाईलैंड	रात 8:00 बजे
31 अगस्त	बांग्लादेश vs इंडोनेशिया	रात 8:00 बजे
1 सितंबर	पाकिस्तान vs थाईलैंड	रात 8:00 बजे
2 सितंबर	श्रीलंका vs इंडोनेशिया	रात 8:00 बजे
3 सितंबर	भारत vs हांगकांग	रात 8:00 बजे
4 सितंबर	यूएई vs इंडोनेशिया	रात 8:00 बजे
5 सितंबर	भारत vs पाकिस्तान	रात 8:00 बजे
6 सितंबर	श्रीलंका vs बांग्लादेश	रात 8:00 बजे
7 सितंबर	पाकिस्तान vs हांगकांग	रात 8:00 बजे
8 सितंबर	बांग्लादेश vs यूएई	रात 8:00 बजे
10 सितंबर	पहला सेमीफाइनल	रात 8:00 बजे
11 सितंबर	दूसरा सेमीफाइनल	रात 8:00 बजे
13 सितंबर	फाइनल	रात 8:00 बजे

ब्रजेश शर्मा 2026/27 घरेलू सीजन से पहले जम्मू-कश्मीर टीम से जुड़े

नई दिल्ली,06 अगस्त 2026। तेज गेंदबाज़ बृजेश शर्मा आने वाले 2026/27 घरेलू सीज़न के लिए जम्मू-कश्मीर की टीम में शामिल हो गए हैं। बृजेश उधमपुर ज़िले के माडा शहर के रहने वाले हैं और इस साल की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में डेब्यू करने के बाद चर्चा में आए थे। हालांकि बृजेश ने आईपीएल 2026 नीलामी के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल के खिलाड़ी के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब वह अपने घरेलू राज्य जम्मू-कश्मीर के लिए खेलने को तैयार हैं, जो मौजूदा रणजी ट्रॉफ़ी चैंपियन है। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के एक भरोसेमंद सूत्र ने गुरुवार को बताया, हां, बृजेश शर्मा रणजी ट्रॉफ़ी के लिए जम्मू-कश्मीर टीम से जुड़ गए हैं। वह तैयारी कैंप के लिए टीम के साथ हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में, बृजेश का नाम जेएण्डके के उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया गया था जो 10-17 अगस्त तक श्रीनगर के एसके स्टेडियम में उत्तराखंड के खिलाफ़ प्रैक्टिस मैच खेलेंगे; दोनों टीमें 8 अगस्त को शहर में रिपोर्ट करेंगी।

साउथ अफ्रीका दौरे पर टी 20आई सीरीज भी खेलेगी भारतीय महिला टीम

जोहान्सबर्ग,06 अगस्त 2026। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को घोषणा की कि दिसंबर 2026 में होने वाले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साउथ अफ्रीका दौरे (जो कई फॉर्मेट वाला दौरा है) के शेड्यूल में तीन मैचों की टी20 आई सीरीज भी जोड़ी गई है। सीएसए के अनुसार, इस शेड्यूल में टी20 आई सीरीज़ को इसलिए जोड़ा गया है ताकि अगले साल होने वाली पहली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी (जो फरवरी 2027 में श्रीलंका में खेली जाएगी) की तैयारी की जा सके। भारत ने इस साल अप्रैल में महिला टी 20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर साउथ अफ्रीका का दौरा किया था और पांच मैचों की टी20आई सीरीज़ खेली थी, लेकिन वे 4-1 से हार गए थे। 9 से 30 दिसंबर तक चलने वाला यह दौरा अब नई जोड़ी गई टी20 आई सीरीज़ के साथ खत्म होगा। 26 दिसंबर को बेनोनी के विलोमूर पार्क में बॉक्सिंग डे टी 20 आई मैच खेला जाएगा। आखिरी दो टी 20 आई मैच क्रमशः 29 और 30 दिसंबर को पॉचेफस्ट्रूम के ओडीआई ओवल में खेले जाएंगे। यह मल्टी-फॉर्मेट दौरा 9 से 12 दिसंबर तक गेबेरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में एक टेस्ट मैच के साथ शुरू होगा। रेड-बॉल मैच के बाद, दोनों टीमें 16 से 22 दिसंबर के बीच पार्ल, केप टाउन और ब्लोमफ़ोन्टिन में तीन मैचों की आईसीसी महिला चैंपियनशिप ओडीआई सीरीज़ खेलेंगी। बदले हुए शेड्यूल का स्वागत करते हुए, सीएसए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोलेट्सी मोसेकी ने कहा, हमें भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के लिए बदले हुए शेड्यूल की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है। इसमें त्योहारों के समय टी 20 इंटरनेशनल सीरीज़ को भी जोड़ा गया है, जिससे यह पक्का होगा कि हमारी प्रोटियाज़ महिला टीम को अगले साल की शुरुआत में श्रीलंका में होने वाली पहली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सबसे अच्छी तैयारी मिल सके।बदले हुए शेड्यूल का स्वागत करते हुए, सीएसए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फोलेट्सी मोसेकी ने कहा, हमें भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के लिए बदले हुए शेड्यूल की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है। इसमें त्योहारों के समय टी 20 इंटरनेशनल सीरीज़ को भी जोड़ा गया है, जिससे यह पक्का होगा कि हमारी प्रोटियाज़ महिला टीम को अगले साल की शुरुआत में श्रीलंका में होने वाली पहली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सबसे अच्छी तैयारी मिल सके।÷

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0)

रा.प्र.क्र. / ब-121 वर्ष .
ग्राम- गंगौटी प.ह.न-07
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रवीण कुमार साहू पिता शिवशम्भू प्रसाद साहू जाति तेली निवासी ग्राम गंगोटी.प.ह.नं....07 रा.नि.म.भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र/पुत्री सुयश साहू..का जन्म / मृत्यु दिनांक 09/12/2013 को ग्राम.गंगौटी में.हुई है,अज्ञानतावश जन्म/मृत्यु पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र/पुत्री सुयश साहू का जन्म / मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत गंगाटी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक17/08/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

आज दिनांक..3/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तहसीलदार
भैयाथान
सील जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0)

रा.प्र.क्र. / ब-121 वर्ष .
ग्राम- गंगौटी प.ह.न-07
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक,प्रवीण कुमार साहू पिता शिवशम्भू प्रसाद साहू जाति तेली निवासी ग्राम गंगौटी,प.ह.न.-07, रा.नि.म.भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र/पुत्री तन्मय साहू का जन्म / मृत्यु दिनांक 26/09/2011 को ग्राम.गंगौटी में हुई है,अज्ञानतावश जन्म / मृत्यु पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र/पुत्री तन्मय साहू का जन्म / मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत गंगोटी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक..17/08/2026 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

आज दिनांक 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

तहसीलदार
भैयाथान
सील जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

खाद्य विभाग का 'सुपरमैन' या व्यवस्था का सुपर मैनेजर?

दस साल... एक ही संभाग! और अब पदोन्नति में भी 'घर वापसी'!

एक अफसर, कई कुर्सियां और नियमों की नई परिभाषा!

2015 से 2025 तक का सफर

- दिसंबर 2015 : खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति
- पहली पदस्थापना : बलरामपुर
- अतिरिक्त प्रभार : सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया
- 2024-25 : सहायक आयुक्त प्रभारी, राज्य खाद्य प्रयोगशाला के प्रभारी भी
- 2025 : पदोन्नति के बाद भी गृह जिला मुख्यालय के पास पदस्थापना !
- 10 साल तक एक ही संभाग के इर्द-गिर्द ड्यूटी

जुगाड़ या योग्यता?

कई कुर्सियां... एक ही अफसर!

जिला प्रभार | अतिरिक्त प्रभार कई जिले | खाद्य प्रयोगशाला प्रभार | सहायक आयुक्त प्रभारी

प्रशासनिक सवाल ?

- क्या एक अधिकारी के पास इतने प्रभार उचित हैं?
- क्या नियमित भर्ती न करके पदोन्नति से पद भरे जा रहे हैं?
- नियमों को बदलकर 'खास' लोगों को फायदा क्यों?

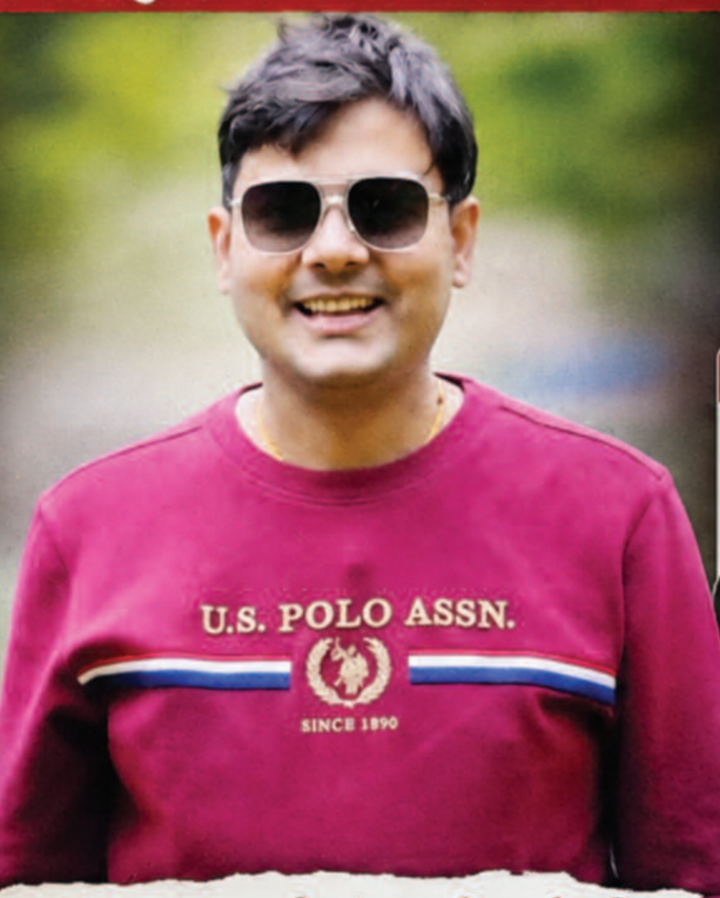

10 साल एक ही संभाग में रहने की ऐसी 'उपलब्धि'... किताबों में नहीं, फाइलों में मिलती है!

प्रयोगशाला में 'अपनों' का बोलबाला?

- राज्य की खाद्य प्रयोगशाला में अपने लोगों की तैनाती
- सैंपल जाए तो रिपोर्ट 'उनके अनुसार' आए?
- नमूना सहायक अर्चना तिवारी (बिलासपुर) का नाम चर्चा में

पदोन्नति का नया खेल?

- पहले 10%... अब 25% पदोन्नति का प्रावधान!
- 12वीं पास नमूना सहायकों को लाभ?
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाने की तैयारी!
- नियम विरुद्ध? सवाल तो उठेंगे!

नियम विपरीत?

स्थापना शाखा पर भी सवाल!

- खाद्य प्रशासन की स्थापना संभाल रहे हैं औषधि विभाग के अधिकारी?
- खाद्य विभाग के अधिकारी कों क्यों नहीं सौंपी जाती स्थापना की जिम्मेदारी?

मंत्री और आयुक्त के संज्ञान में, फिर कार्रवाई क्यों नहीं?

- कई मामले कोर्ट में... कई शिकायतें लंबित...
- आखिर कब होगी निष्पक्ष जांच?

कौन है इस 'सिस्टम' का असली सुपरमैन... और क्यों उड़ रहे हैं सवालों के गुब्बारे?

खाद्य विभाग का 'सुपरमैन' या व्यवस्था का सुपर मैनेजर

एक अफसर, कई कुर्सियां और नियमों की नई परिभाषा!

दस साल तक सरगुजा संभाग से मोह,अतिरिक्त प्रभारों की बरसात,पदोन्नति में भी 'घर वापसी'...आखिर यह प्रशासनिक दक्षता है या अदृश्य जुगाड़ तंत्र?

-न्यूज डेस्क-

अंबिकापुर/रायपुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कहते हैं कि सरकारी नौकरी में तबादला एक ऐसी नियति है,जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है और यदि औषधि एवं खाद्य प्रशासन विभाग में अपवाद खोजा जाए तो चर्चा सबसे पहले नितेश कुमार मिश्रा के नाम से शुरू होती है, आम अधिकारी पांच साल में पांच जिले बदल लेते हैं, लेकिन यदि किसी अधिकारी का पूरा दशक लगभग एक ही जिले में और संभाग के इर्द-गिर्द गुजर जाए अन्य जिले के प्रभार में,तो इसे संयोग कहें, सौभाग्य कहें या फिर 'प्रशासनिक योग्यता' का ऐसा उदाहरण, जिसकी पढ़ाई शायद लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भी नहीं कराई जाती, दिसंबर 2015 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बने और उसके बाद बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया...जिले बदलते रहे, लेकिन संभाग नहीं बदला। ऐसा प्रतीत होता है मानो विभाग ने सरगुजा संभाग की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को नहीं,बल्कि आजीवन पट्टे पर सौंप दी हो।

एक अफसर...कई जिले...और हर जगह वही चेहरा-किसी जिले में मूल पदस्थापना, दूसरे जिले में अतिरिक्त प्रभार, तीसरे जिले में निरीक्षण और चौथे जिले में निर्णय, यदि विभागीय फाइलें बोलने लगें तो शायद यही कहें...'जहां देखो,वहां नितेश मिश्रा,' सरकार को शायद लगा होगा कि जब एक ही अधिकारी इतने काम कर सकता है तो बाकी अधिकारियों की जरूरत ही क्या है? बलरामपुर उनका मूल जिला रहा,सरगुजा अतिरिक्त, सूरजपुर अतिरिक्त,कोरिया अतिरिक्त,फिर प्रमोशन हुआ तो गृह क्षेत्र के आसपास ही नई जिम्मेदारी, इतनी प्रशासनिक निरंतरता तो कई मंत्रियों को भी नसीब नहीं होती।

विभाग का 'ऑल इन वन पैकेज'

सरकारी विभागों में सामान्यत: एक अधिकारी एक पद संभालता है, लेकिन यहां तो कहानी कुछ और ही दिखाई देती है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी...सहायक आयुक्त का प्रभार...प्रयोगशाला का प्रभार...जिलों का अतिरिक्त प्रभार... ऐसा लगता है जैसे विभाग का विज्ञापन हो— 'वन मैन... मल्टीपल सर्विसेज।

प्रयोगशाला भी अपनी... रिपोर्ट भी अपनी?

सूत्रों के अनुसार विभाग के भीतर एक ऐसा प्रभावशाली नेटवर्क काम कर रहा है, जिसकी चर्चा खुलेआम होती है, आरोप यह है कि राज्य की खाद्य प्रयोगशाला में भी ऐसे लोगों को महत्व दिया गया,जिन पर सवाल उठ रहे हैं,यदि यह आरोप सही हैं तो फिर सवाल यह भी है कि—सैंपल कौन लेगा? जांच कौन करेगा? रिपोर्ट कौन बनाएगा? और यदि इन तीनों चरणों पर एक ही प्रभाव हावी हो जाए तो निष्पक्षता कहां बचेगी? हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

नियम बदलते नहीं...बदलवा दिए जाते हैं?- विभाग में पिछले कई वर्षों से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियमित भर्ती नहीं हुई, लेकिन पद खाली भी नहीं रहे, क्योंकि समाधान खोज लिया गया–पदोन्नति,अब आरोप यह है कि नियमों की व्याख्या भी परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही,पहले 10 प्रतिशत,फिर 25 प्रतिशत,फिर नई सूची,फिर नई उम्मीद,और फिर नई बहस, यदि नियम रास्ते में आ जाएं तो शायद नियमों को ही नया रास्ता दिखा दिया जाता है।

स्थापना शाखा का खेल भी कम दिलचस्प नहीं-सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि खाद्य प्रशासन की स्थापना शाखा आखिर खाद्य प्रशासन के अनुभवी अधिकारी क्यों नहीं संभाल रहे? यदि औषधि विभाग का अधिकारी खाद्य विभाग की स्थापना संभालेगा तो विवाद तो उठेंगे ही,यही कारण है कि आज अधिकांश न्यायिक विवाद,शिकायतें और पदोन्नति के प्रश्न खाद्य प्रशासन से जुड़े दिखाई देते हैं, जबकि औषधि विभाग अपेक्षाकृत शांत नजर आता है,क्या यह महज संयोग है? या फिर व्यवस्था में कहीं कोई गंभीर खामी है?

हर शिकायत का अंत... 'जांच जारी है'...

इस विभाग की एक और विशेषता है,शिकायतें आती हैं, समाचार प्रकाशित होते हैं,दस्तावेज सामने आते हैं,मामले न्यायालय तक पहुंचते हैं, लेकिन कार्रवाई? वह शायद किसी लंबी छुट्टी पर चली जाती है,लगता है विभाग का नया आदर्श वाक्य है–शिकायत स्वीकार है, कार्रवाई विचाराधीन है।

इतना प्रभाव आखिर कैसे?

सबसे बड़ा प्रश्न यही है,एक अधिकारी दस वर्षों तक लगभग एक ही संभाग में कैसे बना रहता है? कई जिलों का अतिरिक्त प्रभार कैसे मिलता है? महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बार-बार उसी के हिस्से में कैसे आती हैं? क्या विभाग में उससे अधिक सक्षम अधिकारी नहीं हैं? या फिर व्यवस्था किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होती है?

अब अगला सवाल...संपत्ति और प्रभाव का- यदि किसी अधिकारी का प्रभाव इतना व्यापक बताया जा रहा है कि पदस्थापना से लेकर प्रयोगशाला और पदोन्नति तक उसकी चर्चा हो, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न भी उठता है कि दस वर्षों के इस प्रभावशाली कार्यकाल में क्या-क्या बदला? कौन-कौन सी संपत्तियां अर्जित हुईं? किन-किन लोगों को लाभ मिला? कौन-कौन से फैसले विवादों में आए?

घटती घटना | कोरिया समाचार | अम्बिकापुर मंगलवार 04 अगस्त 2026 | 6

प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला

कथित चूक की शिकायत पर भी नहीं हुई विभागीय जांच!

सरकारी आदेश में 'नमूना सहायक' का नाम दर्ज, शिकायतकर्ता से मांगे सबूत

नितीश कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप

नितीश कुमार मिश्रा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सूरजपुर

क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी शिकायत भी जांच के लायक नहीं थी? रिकॉर्ड सरकार के पास,फिर भी शिकायतकर्ता से मांगे गए साक्ष्य...

सरकारी रिकॉर्ड की जांच करने के बजाय शिकायतकर्ता से मांगे सबूत,उप सचिव की भूमिका पर उठे सवाल...

लेकिन विभाग ने शिकायतकर्ता को ही बुला लिया-

अब सवाल सिर्फ एक अधिकारी का नहीं...

अगले भाग में 'दस वर्षों की कमाई का हिसाब?

नौकरी के बाद कहां-कहां बनी संपत्तियां...किन लोगों से जुड़ा कथित नेटवर्क और विभाग में प्रभाव का पूरा तंत्र...

सोशल मीडिया में डॉ. अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी,आरोपी को हाईकोर्ट से राहत नहीं

बिलासपुर,06 अगस्त 2026। डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भिलाई निवासी अनामिका उपाध्याय (20) को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने एफआईआर,आरोपपत्र और संज्ञान आदेश को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर और गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया

संज्ञेय अपराध बनता है। ऐसे में इस स्तर पर न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन मुद्दों पर अभी कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र में उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की ओर संकेत करती है। इसलिए मामले का परीक्षण ट्रायल कोर्ट में ही होना चाहिए। इसी आधार पर एफआईआर, आरोपपत्र और संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्वीकार्यता,पेन ड्राइव की जब्ती में कथित विसंगतियां,गवाहों की विश्वसनीयता और जांच प्रक्रिया में हुई कथित त्रुटियां तथ्यात्मक विवाद हैं। इन सभी पहलुओं की जांच और मूल्यांकन ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में विकसित भारत जी रामजी योजना लागू,ग्रामीणों को मिलेगा 125 दिन रोजगार

रायपुर,06 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत जी रामजी योजना' को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है,बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, आजीविका के नए अवसर तैयार करना और ग्रामीण विकास को नई दिशा देना भी है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ इस योजना को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि इस योजना के तहत नए प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण परिवारों को अब 125

दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि रोजगार की अवधि बढ़ने से गांवों में रहने वाले लोगों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उन्हें काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके अपने क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत बने। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत कुल 318 प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें सबसे अधिक प्राथमिकता जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को दी गई है। योजना में 107 प्रकार के जल संरक्षण संबंधी कार्य शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इसके अलावा 90 प्रकार के ग्रामीण विकास कार्य भी किए जाएंगे, जिनसे गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। सरकार ने योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके अंतर्गत गांवों में पुस्तकालयों का निर्माण, पशु चिकित्सालयों की स्थापना तथा अन्य आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा,स्वास्थ्य और पशुपालन से जुड़ी सेवाएं बेहतर होंगी। साथ ही गांवों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। योजना में ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्यों को शामिल किया गया है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)